

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> सीएम साय ने नहीं बेटियों ...



मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री बोले

मिलकर काम करें, और तैयारियां मजबूत रखें



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई अहम वरुणत बैठक हुई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए बुलाई गई यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि मौजूदा संकट की वजह से देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा।

पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले

ही देश को आगाह किया था कि मिडिल ईस्ट का यह संकट भारत के लिए लंबी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए, उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने-अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे आम आदमी की जरूरत की चीजों पर कोई आंच न आए। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश संकट में होता है, तो केंद्र और राज्यों को मिलकर एक परिवार की तरह लड़ना पड़ता

है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति की तुलना ठीक 6 साल पहले आई कोरोना महामारी से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोविड-19 के दौरान केंद्र और राज्यों ने %टीम इंडिया% बनकर काम किया था, आज फिर उसी जज्बे की जरूरत है। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त पहली मीटिंग 20 मार्च 2020 को हुई थी, जिसके ठीक चार दिन बाद देश में तीन हफ्ते का लॉकडाउन लगा था। उस मुश्किल दौर में उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा बार मुख्यमंत्रियों से बात की थी ताकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज में कोई कमी न रहे। 2021 में जब वैक्सीनेशन का दौर आया, तब भी पीएम मोदी ने संघीय ढांचे की मजबूती पर भरपूर जताया था। उन्होंने राज्यों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का एलान किया था।



रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत राजधानी रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आज तीसरे दिन पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सभी मैच दिलचस्प और रोमांच से भरे मुकाबले रहे।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज

इयूटी 10-10 रुपए घटी

नईदिल्ली। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज इयूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर इयूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से शून्य कर दी गई है। एक्साइज इयूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है।

यूएस-इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज इयूटी में 10 की कमी की है, जिससे अब यह घटकर 3 प्रति लीटर रह गई है। वहीं, डीजल पर भी 10 की कटौती की गई है, जिससे अब डीजल पर लगने वाली एक्साइज इयूटी जीरो हो गई है। एक्साइज इयूटी कटौती से सरकार का हर दिन का राजस्व करीब 416 करोड़ रुपए घट जाएगा। फ्यूल का प्रकार हर दिन की औसत खपत (करोड़ लीटर में) हर दिन का राजस्व नुकसान (करोड़ रुपए में) इसकी संभावना कम है। भले ही सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। कंपनियां इस छूट का इस्तेमाल अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए करेंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा सह रही हैं। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण तेल कंपनियां महंगा किरूड खरीद रही थीं, लेकिन उन्होंने घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ाए थे। कंपनियां अब इस टैक्स कटौती का इस्तेमाल मार्जिन को स्थिर रखने में करेंगी। तेल कंपनियों के मुनाफे का गणित काफी पेचीदा होता है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की विनिमय दर और सरकार के टैक्स ढांचे पर निर्भर करता है। इन कंपनियों के मुनाफे को समझने के लिए ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन देखा जाता है।

विज्ञान और तकनीक का अनोखा संगम सूर्य तिलक

12 बजे रामलला के माथे पर हुआ चमकदार तिलक

पीएम मोदी सहित करोड़ों श्रद्धालु बने दिव्य सूर्य तिलक के साक्षी

नईदिल्ली। अयोध्या में राम नवमी का पवित्र पर्व अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया गया और राम मंदिर में भव्य सूर्य तिलक समारोह आयोजित हुआ। उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण सूर्य तिलक अनुष्ठान है, जो ठीक दोपहर 12:00 बजे संपन्न होता है। इस अनूठे समारोह के दौरान, मंदिर के भीतर स्थित राम लक्ष्म प्रतिमा के माथे पर वैज्ञानिक विधि से सूर्य की किरण डाली जाती है।

वहीं इस पावन मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम लला से प्रार्थना की और अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह का अवलोकन किया। वैज्ञानिक के द्वारा दर्पणों और लेंसों की उन्नत प्रणाली की बंदीत सूर्य की रोशनी गर्भगृह में प्रवेश करती है और कुछ मिनटों के लिए प्रभु रामलला के माथे पर एक चमकदार तिलक बनाती है। यह समारोह दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और परंपरा एवं आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। भक्तों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित



करने के लिए मंदिर अधिकारियों ने अयोध्या भर में लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, जिस कारण हजारों भक्त इस क्षण के साक्षी बन सके। शुक्रवार सुबह अयोध्या में राम नवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, क्योंकि हजारों लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए पहुंचे। सरयू नदी में पवित्र स्नान करने के बाद, श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में प्रार्थना के लिए उमड़ पड़े। पूरा शहर गहरी

भक्ति के वातावरण में डूबा रहा और जय श्री राम के जयकारे गुंजते रहे। भगवान श्री राम की जयंती मना रहे श्रद्धालुओं में उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की और पुलिस बलों को विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया। अयोध्या मंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि राम नवमी के मौके पर अयोध्या में आस्था की लहर दौड़ गई है, हर जगह श्रद्धालु दिख रहे हैं।

संसद ने आम बजट 2026-27 को मंजूरी दी

नईदिल्ली। संसद ने शुक्रवार को आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आसमान छूने के बीच दो-टूक शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसे लेकर गलतफहमी नहीं फैलायी जानी चाहिए। राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2026-27 को ध्वनिमत से लौटा दिया। इसी के साथ

उच्च सदन ने अनुदान की अनुपूर्क मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इनको पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा



करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है।

लोकसभा की कार्यवाही

रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडारण है और इसे लेकर अफरा-तफरी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि उनकी बृहस्पतिवार को इस विषय पर प्रदेशों के कृषि मंत्रियों से बात हुई है।

महिला आरक्षण कानून में बदलाव पर जल्दबाजी क्यों : खड़गे

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र चल रहा है और सरकार इस सत्र में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाना चाहती है। इसे लेकर अब कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू को पत्र लिखा है। खड़गे ने रिजिजू से पूछा कि सरकार इस कानून में बदलाव के लिए इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि विपक्षी दलों के नेता इस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने 26 मार्च को किरन रिजिजू का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए लिखा कि विपक्षी दलों की ओर से 24 मार्च को ही पत्र लिखकर सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के लिए मतदान हो जाने (29 अप्रैल) के बाद, इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि संविधान संशोधन कानून पारित होने के करीब 30 महीने बाद ही सरकार उसे फिर से संशोधित करने की इतनी जल्दी में क्यों है।

वीरता पुरस्कार पाने वाले जवान करेंगे फ्री रेल यात्रा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने वीरता पदक विजेताओं को बड़ा तोहफा दिया है। सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल से सम्मानित जवानों के साथ ही उनके माता-पिता और जीवनसाथी को भी सरकार ने जीवन भर मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा देने का सरकार ने एलान कर दिया है। सरकार की ओर से गुरुवार को इस संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित जांबाज जवानों के माता-पिता, उनके जीवनसाथी जिंदगी भर भारतीय रेलवे की ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकेंड एसी, एसी चेयर कार में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। विधवा और विधुर अगर फिर से शादी करते हैं, तो इसके बाद उनको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवानों के परिजन एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। गौरतलब है कि सेना के जांबाज जवानों को भारतीय रेल में मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले भी मिलती थी। पहले आजीवन बिना किसी शुल्क का भुगतान किए रेल यात्रा की सुविधा केवल छह वीरता पुरस्कारों से सम्मानित जवानों और उनके परिजनों को ही मिलती थी।



भगोड़े नीरव मोदी की वापसी का रास्ता साफ

नईदिल्ली। भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को लंदन की हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजने का मामला फिर से खोलने की उसकी अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दोबारा खोलने के लिए कोई खास और असाधारण वजह नहीं है। ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सरकारी वकीलों की टीम) ने कोर्ट में नीरव मोदी के खिलाफ बहस की। भारत की छद्म को टीम भी लंदन पहुंचकर इस सुनवाई में मदद कर रही थी। नीरव मोदी ने कोर्ट से कहा था कि कुछ नई बातें हुई हैं, इसलिए मामला फिर से खोलना चाहिए। उसने कहा कि भारत में जेल में उन्हें मारपीट हो सकती है, उसकी जान को खतरा है और जेल की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये नई बातें पुरानी फैसले को बदलने लायक नहीं हैं। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। ही उन्हें भारत लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक (ऋद्ध) घोटाले में निरव मोदी पर 6400 करोड़ रुपये से ज्यादा का गबन करने का आरोप है।



भाजपाई ही कर रहे कालाबाजारी : अखिलेश

लखनऊ। एलपीजी संकट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य जमकर वार-पलटवार हुआ। सपा प्रमुख द्वारा अपने घर में मिट्टी के चूल्हे बनवाने के बयान पर उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि जिसके यहां सिलिंडर न हो वो हमारे यहां सूचना भेज दे, हम सिलिंडर भिजवा देंगे। इसके जवाब में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे हैं। आग्रह है कि वो अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल दें या अपने घर, कार्यालय या फिर सीधे अपने जमाखोरीवाले अंडरग्राउंड गोदाम का पता ही दे दें। शुक्रवार को पार्टी की ओर से जारी बयान में सपा प्रमुख ने भाजपाइयों से सवाल पूछते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सेवा का दावा करने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी अब कहाँ नदारद हैं? गैस और तेल की लाइन में लगे लोगों को समझाने और सिलिंडर व तेल दिलवाने के लिए वो गले में भाजपा का पट्टा और गाड़ियों पर भाजपा का झंडा लगाकर क्यों नहीं निकल रहे हैं।



बालेन शाह ने ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ

काठमांड। रैपर-इंजीनियर बालेन शाह ने शुक्रवार को नेपाल के पीएम पद की शपथ ली। वे 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा पीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल की उपस्थिति में शीतल निवास में दोपहर 12:34 बजे शुभ मुहूर्त पर संपन्न हुआ। सात ब्राह्मणों ने शंखनाद, 108 युवा ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन और 107 लामाओं द्वारा बौद्ध मंत्रों का पाठ किया गया। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में आरएसपी ने भारी बहुमत हासिल किया। पार्टी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीतीं। बालेन शाह ने खुद चार बार पीएम रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा-5 सीट से भारी अंतर से मात दी। नेपाल के आम चुनाव में पारंपरिक बड़े दल बुरी तरह हार गए। नेपाली कांग्रेस को सिर्फ 38 सीटें, सीपीएन-यूएलएल को 25 और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र 17 सीटें मिलीं। करीब छह महीने पहले ओली सरकार को युवाओं के नेतृत्व वाले जेन-जेड आंदोलन में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद हटा दिया गया था।



यूरोप के थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील

आपके सभी से अच्छे रिश्ते... आगे आकर जंग रुकवाएं

नईदिल्ली। दुनिया के कई थिंक टैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरान संकट को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसेस ग्रुप में ईरान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाएज ने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान संकट को सुलझाने के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन एक परिपक्व और अनुभवी राष्ट्र के रूप में भारत इस समस्या का हल निकालने में अहम रोल अदा कर सकता है।

इंटरनेशनल क्राइसेस ग्रुप एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यह दुनिया भर के संघर्षों पर रिपोर्ट और विश्लेषण करता

है, लेकिन यह किसी सरकार या राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। अली वाएज इस संगठन में ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, यानी वे ईरान संबंधी सभी मामलों की अनुवायि करते हैं।

अली वाएज ने ईरान जंग पर कहा कि यह बहुत ही सकारात्मक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनके सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, तनाव कम करने के लिए पहल कर रहे हैं। भारत से और अधिक सक्रियता की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा कि, भारत इससे भी कहीं ज्यादा कर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पड़ने वाले गंभीर असर को देखते हुए अब भारत जैसे नए खिलाड़ियों के लिए यह सही समय है कि वे सभी पक्षों को एक



साथ लाएं और किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश करें।

अली वाएज ने कहा कि फिलहाल युद्धविराम की संभावना कम ही लगती

है, क्योंकि दोनों ही पक्षों को लगता है कि वे अभी भी निर्णायक वार कर सकते हैं। एक परिपक्व और अनुभवी राष्ट्र के तौर पर भारत इसमें एक अहम

भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए वाएज ने ट्रंप द्वारा ईरान पर बड़े हमले करने से हिचकिचाते की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला कर सकते थे, लेकिन ईरान ने भी इसके जवाब में खाड़ी देशों में ऊर्जा और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने से खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों और इजरायल के ग्रीड पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और भी बुरे हालात पैदा हो जाएंगे। इस तरह का एतकवा सिर्फ थोड़े समय के लिए होने वाली नियांत की रुकावटों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे उत्पादन

महीनों या शायद सालों तक ठप हो सकता है। उन्होंने कहा कि कतर पहले ही अपनी प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षमता का 17 फीसदी क्षमता खो चुका है, और इसे ठीक होने में शायद तीन से पांच साल लग सकते हैं। इससे पहले कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट ने भी कहा था कि पीएम मोदी ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा सकते हैं। अमेरिका के युद्ध विशेषज्ञ डगलस मैकग्रेगर ने कहा था कि अगर भारत मध्यस्थता के लिए एनर्जी मार्केट में और भी बुरे हालात पैदा हो जाएंगे। इस तरह का एतकवा सिर्फ थोड़े समय के लिए होने वाली नियांत की रुकावटों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे उत्पादन

से निपटने के लिए किसी भरोसेमंद मध्यस्थ की तलाश उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध को खत्म करना। मैकग्रेगर ने कहा कि अब सवाल सिर्फ प्रभाव का नहीं, बल्कि भरोसे का है कि कौन बंटे गुटों में विश्वास अर्जित कर सकता है। मैकग्रेगर ने कहा कि पीएम मोदी रूस, ईरान, इजरायल और अमेरिका जैसी प्रमुख ताकतों के बीच विश्वास का पुल बनने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत की यह स्थिति इसे विरोधी पक्षों के बीच संवाद का पुल बनने में सक्षम बनाती है। पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता इसे तटस्थ मध्यस्थ बनने से रोकती है।

सरगुजा में नक्सल उन्मूलन ने बदली सरगुजा की तस्वीर

सरगुजा। उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ने विकास में बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 31 मार्च 2026 को पूरे देश में नक्सलवाद का अंत होने जा रहा है।इससे पहले ईटीवी भारत ने सरगुजा में नक्सलवाद के उदय और अंकुश के बारे में जाना। क्योंकि विकास की अवधारणा में निर्माण, कनेक्टिविटी, शिक्षा और व्यापार को ही प्रमुखता से देखा जाता है। लेकिन सरगुजा में इन सभी चीजों को नक्सलवाद ने गहरा आघात पहुंचाया था लेकिन नक्सलवाद के सिमटते ही सरगुजा ने कम समय में वो ऊंचाई हासिल की,जो शायद उसे काफी वर्ष पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी।

नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक जिले से अलग होकर तीन जिले अस्तित्व में आए।



सड़क कनेक्टिविटी शत प्रतिशत हुई। संचार और शिक्षा के माध्यम भी तेजी से बढ़ते गए। लेकिन विकास की इस अवधारणा में यदि सरगुजा आगे बढ़ा तो प्रकृति के संरक्षण में पीछे भी गया क्योंकि यहां गौण खनिजों का दोहन बढ़ा। नक्सलवाद से विकास को कितना नुकसान हुआ इस विषय पर भी हमने कुछ जानकारी से बात की। इस विषय

पर रिटायर्ड एआइजी राजेश्वर सिंह कहते हैं कि नक्सलियों का मकसद यहां पर कोई साम्यवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं था, यहां जो निर्माण कंपनियां थी, जो एजेंसी थी, जो रोड सड़क बनाते थे, बिल्डिंग बनवाते, सरकारी ठेके होते थे, इसके अलावा तैदुपत्ता का जो ठेका होता था, उन ठेकेदारों से लेवी वसूल करना, पैसे वसूल करना

लाल आतंक के कारण ये क्षेत्र काफी पिछड़ गया था

इनका मकसद था। सरगुजा में नक्सलियों का साम्यवाद विचारधारा से कभी दूर दूर तक लेना देना नहीं था।

यहां ना तो कोई कभी शोषण हुआ है, ना बड़े आदमी किसी छोटे आदमी का शोषण किए गरीबों का। तो यहां वैसी आईडियोलॉजी उनको नहीं थी। वो झारखंड से आते थे कुछ दिन के लिए फिर लौट जाते थे। सरगुजा में फैला नक्सलवाद आर्थिक समानता के लिए साम्यवाद का प्रसार नहीं था, बल्कि सरगुजा उनके लिए सिर्फ एक चारागाह और छिपने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। क्योंकि सरगुजा में जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि घने जंगल, पहाड़ दूरस्थ

कस्बे जो नक्सलियों के रहने के लिए मुफीद थे। रिटायर्ड एआइजी राजेश्वर सिंह कहते हैं कि उस समय काम आते थे सरकार से टेंडर निकलता था। लेकिन उनके दहशत से लोग जोखिम नहीं लेते थे और सड़कें पुल पुलिया ये सब बन नहीं पाते थे। जबकि उन्मूलन के बाद तेजी से विकास हुआ। बहुत सारे एनकाउंटर हुए, बहुत सारे नक्सल मारे गए। बहुत सारे गिरफ्तार किए गए। बहुत सारे केस मुकदमे इन पर कायम हुए। जो नक्सलियों को शरण देते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और बहुत से नक्सलाइड मारे गए एनकाउंटर में, इससे इनके पैर उखड़ गए और सजा से इनका उन्मूलन हो पाया।

महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी और लूटपाट मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। तमनार थाना क्षेत्र के सीएचपी चौक, लिबरा में धरना-प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ मारपीट, बदसलूकी और लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्टवाई तेज करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में थाना तमनार में अपराध क्रमांक 309/25 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67(ए) के



तहत जांच की जा रही है। जांच के दौरान पहले ही 7 आरोपियों—मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया, कीर्ति श्रीवास, वनमाली राठिया, कन्हैया राठिया और चित्रसेन साहू—को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना का वीडियो संजय मेहर (26), निवासी मंजना, ने अपने मोबाइल से बनाया था और इसे अपने साथी माधव गुप्ता उर्फ माधो

बोसी (40), निवासी नागरामुंडा, को भेजा था। माधव गुप्ता ने उक्त वीडियो को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, गारे-पेलमा सेक्टर-1 कोयला खदान के विरोध में 12 दिसंबर 2025 से ग्रामीणों द्वारा सीएचपी चौक, लिबरा में आर्थिक नाकेबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। 27 दिसंबर 2025 को जब पुलिस-प्रशासन मार्ग बहाल कराने पहुंचा, तब भीड़ उग्र हो गई और पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस दौरान कई जवान घायल हुए और महिला आरक्षक के साथ गंभीर अपराधिक कृत्य किया गया।

225 किलो मादक पदार्थ जब्त

■ **महासमुंद की सिंधोड़ा पुलिस ने ओडिसा से यूपी ले जाए जा रहे गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है,फलों के नीचे छिपाकर तस्करी हो रही**



महासमुंद। पुलिस ने एक बार फिर मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिंधोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 225 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 1 करोड़ 25 लाख 20 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें गांजा, दो वाहन और मोबाइल फोन शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक 26 मार्च 2026 को एएसआई लक्ष्मण साहू अपनी टीम के साथ ग्राम मुरपुरी क्षेत्र में गश्त और अपराध पतासाजी पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिसा से छत्तीसगढ़ की ओर एक पिकअप वाहन में गांजा लाया जा रहा है, जिसकी पायलटिंग एक कार कर रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम हा।।-53 स्थित ग्राम रेहटीखोल पहुंची और घेराबंदी की। कुछ समय बाद संधिध वाहन आते दिखाई दिए,

जिन्हें रोककर जांच की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सतीश गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, सूरज गुप्ता,योगेश कुशवाहा, हरिबाबु वर्मा और रामबाबु वर्मा बताए।सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पिकअप वाहन में तरबूज के नीचे प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाना स्वीकार किया। तलाशी के दौरान कुल 9 बोरियों में 213 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 225 किलोग्राम निकला। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई। इसके अलावा पुलिस ने पिकअप वाहन अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए,एक कार अनुमानित कीमत 7 लाख और 6 मोबाइल फोन जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिसा के संबलपुर से उत्तरप्रदेश के चित्रकूट ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) एवं 29(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

मेगा फूड पार्क के ऑयल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, वेल्डिंग के दौरान हादसा

■ **फूड पार्क में आग लगने की घटना में तीन मजदूर झुलस गए. जिनका इलाज सीएचसी में चल रहा है.**



धमतरी। कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत बगौद स्थित नैविक ऑयल एंड साल्वेंट मेगा फूड पार्क में देर रात आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लांट परिसर में चल रहे वेल्डिंग कार्य के दौरान हुआ, जहां अचानक चिंगारी भड़कने से आग फैल गई।

बगौद स्थित मेगा फूड पार्क में धान के भूसे से राइस ब्रॉड खाद्य तेल निर्माण का कार्य किया जाता है। गुरुवार देर रात प्लांट के एक हिस्से में मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान निकली चिंगारी ने आसपास मौजूद ज्वलनशील सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग भड़क उठी।

आग लगते ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची

और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

हादसे में तीन मजदूरों के हाथ और पैर झुलस गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एहतियातन सीएचसी कुरुद भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। आग पर जल्द नियंत्रण होने के कारण प्लांट के अन्य हिस्सों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा।

डोरसपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कुरुद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग कार्य के दौरान

सुरक्षा मानकों में लापरवाही को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग अब सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच कर रहे हैं। घटना में घायल मजदूरों की स्थिति फिलहाल सामान्य है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मेगा फूड पार्क में ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी के कारण आग फैलने का खतरा ज्यादा था, लेकिन दमकल विभाग की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई और किसी बड़ी जनहानि से बचाव हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और प्लांट प्रबंधन से भी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी ली जा रही है।

सूरजपुर के प्रतापपुर में एसईसीएल के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला.ग्रामीण जबरन जमीन अधिग्रहण और मकान तोड़ने का आरोप लगा रहे थे.

सूरजपुर। प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर ओपन माईंस के सामने ग्रामीणों का आंदोलन करीब 8 से 10 घंटे बाद स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीणों कोल माईंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे,जिसे प्रशासन और एसईसीएल के अफसरों ने मौके पर जाकर समझा और ग्रामीणों को समझाइश दी। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। ग्रामीणों ने एसईसीएल पर जबरन भूमि अधिग्रहण करने और मकान तोड़े जाने का आरोप लगाया। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे, जिससे कोयला परिवहन भी कई घंटों तक प्रभावित रहा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह अपने



समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित

कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर विरोध जताया।

जगन्नाथपुर में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मंजु मिंज के मकान तोड़े जाने के खिलाफ एसईसीएल के खिलाफ हम सभी आए हैं हमारे आंदोलन को जिला कांग्रेस का समर्थन मिला है। हमने एसईसीएल को कहा है कि जब तक जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रबंधन गांव वालों की मांगों को पूरा नहीं करते हम आंदोलन को जारी रखेंगे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, पुलिस बल, एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। काफी समझाइश के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को एक जापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई कि कलेक्टर और

एसईसीएल के जीएम के साथ एक संयुक्त समिति बनाई जाए। समिति में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। बैठक और सहमति के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। ग्रामीणों ने बातचीत और समिति गठन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

गौरतलब है कि विवाद उस समय बढ़ गया जब एसईसीएल ने अधिग्रहित क्षेत्र में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजु मिंज का मकान तोड़ा। इसके बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी फैल गई और उन्होंने जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

बच्ची से दुर्व्यवहार पर प्राचार्य पर लगा 50 हजार का जुर्माना

दुर्ग। नंदिनी थाना क्षेत्र में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी की एक मासूम बच्ची के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में अब शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। करीब साढ़े तीन साल की बच्ची से अमानवीय व्यवहार के इस मामले में स्कूल की प्राचार्य ईला ईवन कोलविन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। यह घटना जुलाई 2025 की बताई जा रही है। आरोप है कि नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची ने स्कूल में राधे-राधे कहा, जिससे प्राचार्य नाराज हो गईं। इसके बाद उन्होंने बच्ची को डाटा-फटका ही नहीं, बल्कि कथित तौर पर उसके साथ मारपीट भी की और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। जब बच्ची घर पहुंची तो वह डरी-सहमी हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार में आक्रोश फैल गया। बच्ची के पिता प्रवीण यादव ने तुरंत नंदिनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

प्रभारी ने डकारा 70 लाख का धान, खरीदी प्रभारी गिरफ्तार

कबीरधाम। कबीरधर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित पेण्ड्रीकला धान खरीदी केंद्र में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां 70.43 लाख रुपये से अधिक की धान हेराफेरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने खरीदी प्रभारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी की प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव शाखा कुण्डा के माध्यम से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसने मामले की पड़ताल की गई। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। रिकॉर्ड के अनुसार 12 जनवरी 2026 तक केंद्र में 23,319.20 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की थी। इसमें से 3,880 क्विंटल धान का उठाव हो चुका था। शेष 19,439.20 क्विंटल धान केंद्र में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया, तो मौके पर मात्र 17,167.20 क्विंटल धान ही मिला।

गढ़कलेवा चौपाटी में सिलिंडर चोरी कर हुए फटार

कोरबा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत घंटाघर स्थित गढ़कलेवा चौपाटी में अज्ञात चोरों ने दो दुकानों से गैस सिलिंडर चुरा लिए। शुक्रवार सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो इस घटना की जानकारी हुई। चोरों ने दुकानों में रखे पैसे और अन्य कीमती सामान को छुआ तक नहीं, केवल गैस सिलिंडर पर हाथ साफ किया। इस घटना ने चौपाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौपाटी संघ के अध्यक्ष रवि वर्मा ने बताया कि चौपाटी में लगभग 60 से अधिक दुकानें हैं, इसमें कई लोगों का परिवार चलता है। जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मनोज फास्टफूड और जगदीश की दुकान पर चोरी की घटना का अंजाम दिया है। जहां से नगदी रकम न ले जाकर के केवल गैस सिलिंडर की चोरी कर ले गए हैं, इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस से की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गैस सिलिंडर को लेकर काफी क्ललत है जो बड़ी आसानी से नहीं मिल पा रही है। मिल भी रही है तो अवैध तरीके से अधिक दामों पर उपलब्ध हो रहे हैं।

लूटी चैन को बैंक में गिरती रखने वाले 2 शातिर गिरफ्तार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में युवती से चैन लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने लुटेरों को पकड़ा। दोनों बदमाशों ने लूटी हुई चैन एक निजी बैंक में गिरवी रखकर 80 हजार रुपए का गोल्ड लोन ले लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि, लिंक रोड पर वैष्णवी विहार निवासी युवती अपने भाई के साथ 23 मार्च को रात रेलवे स्टेशन से घर लौट रही थीं। इस दौरान रामा पोर्ट के पास उनकी स्कूटी पंक्कर हो गई। दोनों भाई-बहन धीरे-धीरे स्कूटी चलाकर घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी दो लुटेरों ने उनका पीछा किया और मदद के बहाने चैन छीनने के बाद आरोपी शेख सलमान डिवाइडर कूटकर और साथी आकाश नायक बाइक चालू कर भाग निकली। युवती की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपी इलेक्ट्रिक ऑटो में घूमते दिखा। इसके बाद साइबर सेल की तकनीकी मदद से पता चला कि आरोपी देवरीखुर्द और तापबाहर क्षेत्र में छिपे हैं।

एक दूल्हे ने दो दुल्हनों संग एक ही मंडप में लिए सात फेरे

कोंडगांव। बस्तर अंचल की लोक संस्कृति और परंपराएं अक्सर दुनिया को चौंकाती रही हैं। इसी कड़ी में जिले के फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बैलगांव से एक विवाह सामने आया है, जिसमें एक युवक ने दो युवतियों के साथ एक ही मंडप में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए। इस अनोखी शादी का निमंत्रण पत्र (कार्ड) और शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कार्ड में एक दूल्हे के साथ दो दुल्हनों के नाम छपे हैं। वहीं वायरल वीडियो में दूल्हा अपनी दोनों दुल्हनों का हाथ थामे अग्निके फेरे लेते और रस्में निभाते हुए दिख रहे। वहीं दूल्हे के दोस्तों और ग्रामीणों ने शादी में जमकर डांस किया, जिससे यह विवाह किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों परिवारों की आपसी सहमति और समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से यह शादी हुई, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। हालांकि मुख्यधारा के कानून में द्विपत्नी विवाह को मान्यता नहीं है।

धान की जगह मूंगफली लगाकर किसान ज्यादा खुश

कोरबा। परंपरा का तौर पर उगाये जाने वाले धान की जगह पर किसान अब अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की भी यह मंशा है कि धान की फसल को हतोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तिलहन और दलहन की फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान के स्थान पर अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कोरबा जिले के दादर गांव के किसान नंदकुमार भी अब तक धान की खेती करते आ रहे थे। मुनाफा कम होता था, कई बार नुकसान भी हुआ। अब नंदकुमार ने धान की फसल को मूंगफली में परिवर्तित कर दिया है। नंदकुमार



को कृषि विभाग से निशुल्क बीज भी मिले हैं। पैदावार भी अच्छी है, किसान काफी खुश है। मूंगफली कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। खासतौर पर उन खेतों के लिए जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहां के लिए ऐसी फसलें किसी वरदान से कम नहीं हैं। बिना पानी और ज्यादा मेहनत के मूंगफली की फसल अच्छा मुनाफा देती है। पैदावार अच्छी हुई तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक मूंगफली उगाई जा सकती है। प्रति

क्विंटल का दाम भी 6000 तक पहुंच जाता है। जो समर्थन मूल्य पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत से कहीं अधिक है। मूंगफली की खेती के लिए हल्की, रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जिसमें लाल निकासी अच्छी हो। इसकी खेती खरीफ और रबी सीजन के बीच में की जाती है। प्रति एकड़ लगभग 15-20 क्विंटल उत्पादन मिल सकता है। मूंगफली की खेती किसानों के लिए एक अत्यधिक लाभदायक और बहुउद्देशीय फसल है। जो कम लागत में 120-150 दिनों में अच्छी आय देती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता में इजाफा करने की क्षमता होती है।

कोरिया कॉलरी में 5.51 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

■ **मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने चैत्र नवरात्रि पर एमसीबी और कोरिया जिले को बड़ी सौगात दी.**



मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ अंतर्गत चैनपुर में गुरुवार को जिला पंचायत के नए भवन का विधिवत भूमिपूजन संपन्न हुआ। लगभग 3 करोड़ 1 लाख 32 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस बहुप्रतीक्षित भवन का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने पूजा-अर्चना के साथ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पहले जिले के केवल नाम के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक

व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। जिले में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और एसपी की पदस्थापना से प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हुआ है। मंत्री ने जानकारी दी कि सीएमएचओ कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि जल्द ही कलेक्ट्रेट भवन का भी भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने नए जिला पंचायत भवन को नवगठित जिले के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर बताया। जायसवाल ने यह भी बताया कि भवन का स्थान इस प्रकार चुना गया है कि

खड़गांव, केलहारी, जनकपुर और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों को समान दूरी तय करनी पड़े, जिससे आम जनता को अधिक सुविधा मिल सके।लग्नां अष्टमी के पावन अवसर पर हुए इस भूमिपूजन को उन्होंने शुभ संयोग बताते हुए क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया। वहीं चिरमिरी के कोरिया कॉलरी क्षेत्र में भी लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को लेकर बड़ी सौगात दी गई। यहां लगभग 5 करोड़ 51 लाख 9 हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से सिद्धबाबा मंदिर तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं, जिसकी मांग वर्षों से की जा रही थी। खराब सड़क के कारण श्रद्धालुओं को विशेषकर बरसात के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कार्यक्रम में निगम महापौर रामनरेश राय, सभापति संतोष सिंह, एमआईसी सदस्य, वार्ड पार्षद,

भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरिया कॉलरी क्षेत्र के लोगों की यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर उद्यान योजना के तहत इस सड़क सहित अन्य विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि शांखा शिव मंदिर के लिए लगभग 3।5 करोड़ रुपये की लागत से भव्य निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। इसके अलावा शाखा उद्यान के सौंदर्यीकरण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी बात करते हुए कहा कि अस्पताल की समस्या अब दूर हो चुकी है और जलापूर्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

जसगीतों के साथ हुआ जोत जंवारा का विसर्जन, भक्तों की उमड़ी भीड़

रायपुर। गुरुवार को हवन के पश्चात शुक्रवार



की सुबह से जसगीतों के साथ जोत जंवारा विसर्जन शुरू हो गया। शहर के सबसे पुराना कंकाली तालाब में जंवारा विसर्जन देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के अलग-अलग हिस्सों जिसमें आमापारा, केलकपारा, बढाईपारा, मंगलबाजार से जोत जंवारा के साथ बड़ी संख्या में भक्त सांग लिए हुए थे जो जसगीत की धुन में झुम रहे थे। इसके साथ ही नवरात्र पर्व पर उपवास रखने वाले भक्तों ने सुबह मंदिरों में पहुंचकर मां की पूजा-अर्चना कर उपवास का समापन किया। वहीं नवरात्र पर्व को लेकर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं चिलचिलाती धूप व गर्मी से बचने के लिए मंदिर समिति व श्रद्धालु भक्त सुबह से ही जोत जंवारा व सांग धारण किए भक्तो के पैरों में छाला ना पड़ जाए लिए लिए जगह-जगह पर पानी की बौछारे कर रहे थे। कंकाली तालाब में पहुंचने के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ज्योति कलश विसर्जित किया गया।

10 अप्रैल से आत्मानंद स्कूलों में शुरु होगा प्रवेश प्रक्रिया

रायपुर। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। प्रदेश में वर्तमान में 403 अंग्रेजी माध्यम और 348 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, जिनमें नए सत्र के लिए प्रवेश दिए जाएंगे। रायपुर जिले में 36 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं। यदि किसी विद्यालय में सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो छात्रों का चयन कंप्यूटर आधारित लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया 6 मई से 10 मई 2026 के बीच पूरी की जाएगी, जबकि अन्य प्रवेश संबंधी कार्यवाही 11 मई से 15 मई तक की जाएगी। सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा। यदि छात्राओं की संख्या कम रहती है, तो इन सीटों को छात्रों से भरा जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही विद्यालय में आवेदन कर सकेगा।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की सट्टेबाजों को सख्त चेतावनी, कानून के साथ मत खेलना

रायपुर। आईपीएल शुरू होने से पहले रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की सट्टेबाजों के लिए खास संदेश जारी की है। ‘कानून के साथ मत खेलना’, वरना मैच ही नहीं, जेल भी देखनी पड़ेगी। दरअसल, हर साल आईपीएल के मैच के दौरान सट्टेबाजी बड़े पैमाने पर होती है। पुलिस हर बार कार्रवाई करती है, लेकिन सट्टेबाजों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि कारोबार चलता ही रहता है। अबकी बार आईपीएल शुरू होने से पहले रायपुर पुलिस कमिश्नरेट इस पर लगाम कसने के लिए सक्रिय है। इस दिशा में सोशल मीडिया में बाकायदा मैसेज जारी कर सट्टेबाजों को चेतावनी दी है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने क्रिकेट की भाषा में समझाया है कि बेटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। ‘चेज’ करने में माहिर है कानून की टीम। फर्जी सट्टा आईडी देने वालों से दूरी बनाने की अपील, नहीं माने तो ‘पार्टनरशिप’ नहीं टिकेगी इसके साथ ही रायपुर पुलिस ने साफ संदेश दिया है। सट्टेबाजी छोड़िए, वरना सीधा जेल का रास्ता।

गहने चोरी का आरोप, कर्मचारी ने कहा- 8 घंटे तक बंधक बनाकर संचालक ने पीटा

रायपुर। राजधानी के सदर बाजार स्थित



सहेली ज्वेलर्स शॉप में उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब दुकान के कर्मचारी आर्यन शर्मा पर लाखों के गहनों की चोरी का आरोप लगाया गया। वहीं कर्मचारी आर्यन का आरोप है कि उसे दुकान में बंधक बनाकर 8 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, सहेली ज्वेलर्स के संचालक ने कर्मचारी पर करीब 6.49 लाख रुपये के आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी को गहने जेब में रखते हुए देखा गया है। दुकान प्रबंधन का दावा है कि पूछताछ के दौरान कर्मचारी ने चोरी की बात स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने गहने वापस कर दिए। वहीं कर्मचारी आर्यन शर्मा ने सहेली ज्वेलर्स के संचालक पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसे बंधक बनाकर करीब 8 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया। साथ ही उसकी मां से जेवर मंगवाकर छोड़ने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक ही घटना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती पर भाजपा-कांग्रेस में सियासी संग्राम

■ रामनवमी का तोहफा बनाम चुनावी मजबूरी

रायपुर। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती के बाद देशभर में जहां आम जनता को राहत मिली है, वहीं सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। भाजपा इसे रामनवमी का तोहफा और प्रधानमंत्री का जनहितकारी फैसला बता रही है, तो कांग्रेस इसे चुनावी मजबूरी और पुरानी वसूली की भरपाई करार दे रही है। फैसले से ज्यादा अब नेताओं के बयान सुर्खियों में हैं।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को बड़ा और स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच जनता को राहत देने का काम किया है। अरुण साव ने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर यह फैसला देशवासियों के लिए तोहफा है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस मोडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि डीजल को एक्साइज से मुक्त करना और पेट्रोल पर कटौती करना कोई एहसान नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया निर्णय है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरोना



काल में पेट्रोल-डीजल पर भारी एक्साइज ड्यूटी लगाकर सरकार ने बड़ी कमाई की थी। उनके मुताबिक, मौजूदा कटौती उसी वसूली की आंशिक वापसी है, इसे नई राहत नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि जैसे ही मतदान खत्म होगा, पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे।

एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम जनता को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस फैसले ने आर्थिक राहत से ज्यादा सियासी बहस को हवा दे दी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती ने जहां लोगों को राहत दी है, वहीं तोहफा बनाम मजबूरी की इस बहस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि यह राहत कितनी स्थायी रहती है।

प्रभु राम को काल्पनिक ना मानकर

मनाएं रामनवमी : पुरंदर मिश्रा

रायपुर। विधायक पुरंदर मिश्रा ने देशवासियों को रामनवमी पर्व की बधाई देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, सभी को रामनवमी का पर्व मनाना चाहिए। खासकर रामनवमी पर कांग्रेस को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो रहा है। प्रभु राम को काल्पनिक ना मानकर रामनवमी मनाएं। भगवान से सद्बुद्धि की मांग करें, ताकि वे मजबूत विपक्ष के रूप में बने रहे।

कांग्रेस पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन करेगी। इस मामले में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस बोलती कुछ और करती कुछ है। अब तक प्रदेश, ब्लॉक, मंडल का गठन नहीं कर पाई है। पंचायतों में कमेटेी का गठन करना कांग्रेस के लिए असंभव है इसलिए कांग्रेस



में आलू से सोना निकलता है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार खिसक चुका है।

छत्तीसगढ़ के जेलों में 285 कैदियों की मौत मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। इस मामले पर कांग्रेस को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो रहा है। प्रभु राम को आखें खुली है, कान से भी जोर से सुन रहे हैं, तभी छत्तीसगढ़ प्रदेश चल रहा है। कई अपराधी जेल में हैं, जितना उनको जीवन दिया है उतना अपराधी जिएगा। यह एक प्रक्रिया है। हमको इसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। जो जेल में हैं और जेल से बाहर है उन्हें लंबी उम्र भगवान दे। शासन अपने स्तर पर काम कर रही है। जो भी काम में गड़बड़ी करेगा उसे साथ सरकार नहीं छोड़ेगी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के आएंगे अच्छे दिन

युक्तियुक्तकरण विवाद हो सकता है खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर शालेय शिक्षक संघ और शिक्षामंत्री गजेन्द्र यादव के बीच अहम बैठक हुई। संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने टीईटी अनिवार्यता, भर्ती-पदोन्नति नियम 2026, युक्तियुक्तकरण और विभागीय परीक्षाओं जैसे कई मुद्दों को उठाया। बैठक में मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अधिकारियों को तुरंत प्रतिभागशील खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों में रोमांच भर दिया।

शालेय शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। संघ ने मांग रखी कि आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए, वहीं अब में नियुक्त शिक्षकों के लिए सरल विभागीय परीक्षा का विकल्प दिया जाए। इस पर शिक्षामंत्री



ने भरोसा दिलाया कि किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जाएगा और संतुलित व्यवस्था बनाई जाएगी। संघ ने नए भर्ती-पदोन्नति नियम 2026 को लेकर नाराजगी जताई। आरोप लगाया गया कि यह नियम एलबी संवर्ग के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के साथ पक्षपात करता नजर आ रहा है और किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास है।मंत्री ने इस मुद्दे पर संगठन से विस्तृत सुझाव मांगे और सुधार की दिशा में कार्यवाही का आश्वासन दिया।

युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने मांग की कि इस प्रक्रिया को

नस्तीबद्ध कर पीड़ित शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस रखा जाए और लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। शिक्षामंत्री ने इस पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया।

संघ ने प्राचार्य के 10% पदों पर शीघ्र विभागीय परीक्षा आयोजित करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे पदोन्नति की राह खुलने की उम्मीद है।

पूरी बैठक को सकारात्मक और विस्तृत बताया गया। वीरेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार के रुख से उम्मीद जगी है कि जल्द ही ठोस निर्णय सामने आएंगे। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से सभी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर हुई यह बैठक फिलहाल राहत भरी खबर लेकर आई है। अब नजर सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी है, जो लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेंगे।

श्रीराम नवमी पर ऐतिहासिक निर्णय के लिए किरण देव ने माना केन्द्र सरकार का आभार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष

किरण देव ने पेट्रोल और डीजल पर भारी कटौती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूरी केन्द्र सरकार के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार माना है और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रू. घटाकर मात्र 3 रू. कर दिया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क पूरी तरह समाप्त कर शून्य कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी केन्द्र सरकार ने यह निर्णायक कदम सुनिश्चित किया है कि आम उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने से इसका लाभ देश की 140 करोड़ जनता को होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकट के दौर में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया है इसके लिए पुनः केन्द्र की मोदी सरकार को बधाई।

नदी में तटबंध निर्माण से सुरक्षित होंगे घर : विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री ने 4.08 करोड़ रूपए की लागत के सकटी नदी तटबंध निर्माण का किया भूमिपूजन

रायपुर। सकरी नदी में कटाव को रोकने और ग्रामीणों को बाढ़ से सुरक्षा देने के उद्देश्य से आज ग्राम कोडार में 4.08 करोड़ रुपए की लागत से 250 मीटर लंबे तटबंध निर्माण कार्य का भूमिपूजन उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना से ग्राम कोडार के नदी किनारे बसे मकान सुरक्षित होंगे, कटाव की समस्या पर नियंत्रण मिलेगा और ग्रामीणों को निस्तारी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम रेगाखार पंचायत के आश्रित ग्राम कोडार में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सकरी नदी के किनारे लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी, जिसे ध्यान में



रखते हुए इस तटबंध निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि 250 मीटर लंबा यह तटबंध न केवल नदी के कटाव को रोकेगा, बल्कि बाढ़ के दौरान पानी के दबाव से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। इससे नदी किनारे बसे घर सुरक्षित रहेंगे और लोगों को बार-बार होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। साथ ही, नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए निस्तारी की सुविधाएं भी बेहतर होंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम में 142 आवास स्वीकृत किए गए हैं

सचिव प्रसन्ना ने की कृषि विभाग की समीक्षा

खाद-बीज की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

रायपुर। राज्यपाल के सचिव एवं सहकारिता सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना खरीफ सीजन की तैयारियों, उर्वरक की निबांध आपूर्ति, बीज की उपलब्धता और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की गई। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को राहत और बोमा क्लेम का त्वरित रूप से दिलाने के निर्देश दिए गए।

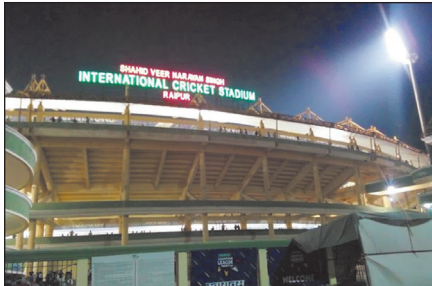
सूरजपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, संयुक्त कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, एस.डी.एम. श्री अजय मोडियम, उपसंचालक कृषि सुश्री सम्पदा पैकरा सहित कृषि विभाग से सम्बद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव श्री प्रसन्ना बैठक में पूर्व वर्षों में उर्वरकों की मांग और आपूर्ति की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली गई तथा वर्तमान खाद भंडारण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने आगामी खरीफ सीजन 2026-27 के लिए जिले में गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रासायनिक उर्वरक का पर्याप्त भंडारण



किया जाए और रैंक पॉइंट से आवॉरिंट खाद का जिले में समय पर भंडारण सुनिश्चित हो।

प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियों में भंडारण व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए। खाद एवं बीज निरीक्षकों द्वारा बीज व खाद दुकानों तथा समितियों का नियमित भौतिक निरीक्षण किया जाए, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी स्थिति पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि खाद का वितरण नियमानुसार हो और केवल पात्र किसानों को ही खाद व बीज उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिये उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाने और क्रियान्वयन की बात कही।



की जाएगी। मैच से पहले आरसीबी की टीम शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आईपीएल-2026 के दो मैच होंगे। दोनों मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू (आरसीबी) के घरेलू मैच होंगे। 10 मई को आरसीबी के सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती होगी। वहीं, दूसरा मैच 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7.30 बजे से फ्लड लाइट में खेले जाएंगे और क्रिकेटप्रेमियों को चौके-छक्कों की बौछर देखने को मिलेगा।

रायपुर के मैदान पर न केवल विराट कोहली का बल्ला गरजेगा, बल्कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान की मौजूदगी की भी पूरी संभावना है। सीएससीएस के अनुसार स्टेडियम में वीआईपी स्टैंड की सीटों में बढ़ोतरी

व्यवस्था हो सकेगी। नई जगह पर बड़ी और आधुनिक स्क्वीन लगाई जाएंगी, जिनसे दर्शकों को स्लो मोशन और मैच के रोमांचक पल बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे।

ये सितारे आएंगे रायपुर

आरसीबी- विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल साल्ट, कुणाल पांड्या, टिम डेविड, जैकब बैथेल, कनिष्ठ चिट्ठम, विहान मल्होत्रा, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल।

मुंबई इंडियंस- रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, क्रिंटन डी कॉक, रयान रिक्लेक्शन, हार्दिक पांड्या, मिशेल सेंनटर, ट्रेट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर।

केकेआर- अजिंक्य राहणे, रिंकू लगी दोनों स्क्वीन हटाने की योजना है। सीएससीएस के अनुसार स्टेडियम में वीआईपी स्टैंड की सीटों में बढ़ोतरी

सिंह, आर पावेल, टिम शेनटन, रचिन रविंद्र, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा।

मध्य पूर्व में युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

देवेन्द्र कुमार बुडकोटी

पश्चिम एशिया में अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े चल रहे संघर्ष के वैश्विक प्रभाव हैं। भारत में इसका असर पहले से ही दिखाई देने लगा है, जहाँ खाना पकाने वाली गैस की घबराहट में खरीदारी और कालाबाजारी की घटनाएँ सामने आई हैं, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि पर्याप्त भंडार होने के कारण फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। हालाँकि, इससे जो बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आता है, वह है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। इस संघर्ष ने नागरिकों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं, आपूर्ति की कमजोरियों और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता के प्रति अधिक जागरूक किया है। वर्षों से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश करने के प्रयास कर रहा है। इनमें सौर, पवन, ज्वारीय, परमाणु और जलविद्युत ऊर्जा शामिल हैं, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में। ये पहल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाती हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर शीघ्र संक्रमण की आवश्यकता के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं। इस संकट ने कुछ महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को भी उजागर किया है, जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व, जहाँ से विश्व के लगभग पाँचवें हिस्से के तेल की आपूर्ति और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। इस महत्वपूर्ण मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है, जिसका विशेष प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ेगा। भारत में ऊर्जा सुरक्षा को अक्सर पेट्रोलियम, तेल और स्लेक में आत्मनिर्भरता की कमी के संदर्भ में समझा जाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 82% आयात करता है, जिससे वह विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन जाता है। इस खपत का बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है—दो-पहिया और यात्री वाहनों के लिए पेट्रोल, ट्रकों और बसों के लिए डीजल, विमानन ईंधन, तथा कृषि में उपयोग। इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की पहल की है, जिसमें दो-पहिया वाहन, कारें, बसें और औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य ऋद्धर की खपत और आयात निर्भरता को कम करना है। भारत का ऊर्जा परिदृश्य एक रणनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा है। 2025 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 217 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, और वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता का लगभग 49% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों, जिसमें नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं, से आता है। राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलें इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है। वर्तमान मध्य पूर्व संकट से पहले ही भारत ने रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली थी, अक्सर रुपये-आधारित व्यापार जैसे अनुकूल प्रबंधों के माध्यम से, जो उसके आर्थिक और ऊर्जा हितों के अनुरूप था। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान कुछ देशों द्वारा आलोचना के बावजूद, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। भारत अमेरिका और इज़राइल जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है, साथ ही ईरान के साथ ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध भी कायम रखता है। तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, भारत की संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति उसकी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(ख) वेद में आदित्य (सूर्य) को ही जार कहते हैं क्योंकि वह रात को जोणं परिसमाप्त= खत्म करने वाला है।

आर्यसमाज-प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उक्त रूपक का समर्थन किया है यथा-

इन्द्रः सूर्यो य एष तपति, भूमिस्थान्पदार्थांश्च

प्रकाशयति।

अस्येन्द्रेति नाम परमैश्वर्य्यप्राप्तेर्हेतुत्वात्।

स अहम्यस्या जारोऽस्ति।

सा सोमस्य स्त्री तस्य गोच-मेति नाम।

गच्छतीति गौरितथिवेन गौरिति गोत्तम-श्वन्द्रः।

तयोः स्त्रीपुरुषवत् सम्बन्धोस्ति।

अत्र स सूर्य्य इन्द्रो रात्रेरहल्याया गोत्तमस्य

चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते।

कुतः श्रयं रात्रेरञ्जयिता।

जुष् वयो-हानाविति धात्वर्थोऽभिप्रेतोऽस्ति।

राजेरायुषो विनाशक इन्द्रः सूर्य्यै एवेति मतव्यम्।।

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ 300)

अर्थात्- [दयानन्त्रीय भाषार्थ अहल्या तथा चन्द्रमा का गोत्तम है। पुरुष के समान- रूपकालङ्कार है। सूर्य्य का नाम इन्द्र, रात्रि का यहां रात्रि और चन्द्रमा का स्त्री इस रात्रि का जार श्रादित्य है।

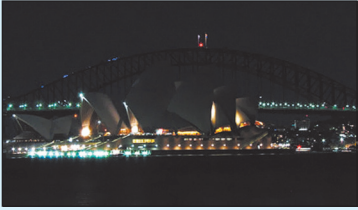
अर्थात्- जिसके उदय होने से रात्रि अन्तर्धान हो जाती है और जार अर्थात् यह सूर्य्य ही रात्रि के वर्तमान रूप शृङ्गार को बिगाड़ने वाला है। जैसे स्त्री पुरुष मिल कर रहते हैं वैसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चन्द्रमा का नाम गोत्तम इसलिये है कि वह और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं कि तथा सूर्य्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, कहता है इत्यादि (ऋग्वेदादि० भू० अत्यन्त वेग से चलता है उसमें दिन लय हो जाता है इसलिए यह उसका जार पृष्ठ 301)

क्रमशः ...



दिलीप कुमार पाठक

प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता आदिकाल से एक अटूट डोर से बंधा रहा है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उस डोर को इतना खींच दिया है कि अब उसके टूटने की आहट साफ सुनाई देने लगी है। इसी आहट को पहचानने और दुनिया को एक धागे में पिरोने का नाम है—अर्थ ऑवर। हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी मर्जी से अपने घरों और दफ्तरों की लाइटें एक घंटे के लिए बंद कर देते हैं। यह केवल बिजली बचाने का कोई तकनीकी काम नहीं है, बल्कि यह धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता और चिंता का एक सामूहिक प्रदर्शन है। 28 मार्च की वह शाम जब घड़ी की सुइयां एक खास वक पर आकर ठहरेंगी और शहर की चकाचौंध को



एक सुकून भरी खामोशी निगल लेगी, तब वह अंधेरा हमें डराएगा नहीं, बल्कि हमें आईना दिखाएगा।

सोचिए, जिस सूरज की रोशनी और जिस हवा के झोंकों ने हमें जीवन दिया, आज वही हवा जहरीली हो रही है और वही मौसम बेईमान हो चुके हैं। हम एक ऐसी सभ्यता बन गए हैं जिसने उजाले की इतनी हसरत पाल ली कि हम सितारों भरी काली रातों का सौंदर्य ही भूल गए। अर्थ ऑवर नहीं उसी प्राकृतिक सौंदर्य की याद दिलाता है। यह साठ मिनट का समय हमें

ऑवर का वैश्विक संकलप

सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तपती हुई धरती छोड़कर जा रहे हैं या एक सुरक्षित आशियाना? जब पेरिस के एफिल टॉवर से लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक की लाइटें गुल होती हैं, तो संदेश साफ़ होता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, कुदरत के नियमों से ऊपर नहीं हैं। नदी जैसे बहते इस जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर छोटी बूंद समंदर बनाती है। कई लोग सवाल करते हैं कि महज एक घंटा लाइट बंद करने से क्या होगा? क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी? जवाब है—शायद तुरंत नहीं, लेकिन यह एक घंटा हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए काफी है। यह एक ऐसी प्रतीकात्मक शुरुआत है जो हमें बताती है कि अगर हम एक घंटे के लिए पूरी दुनिया के साथ एकजुट हो सकते

हैं, तो हम साल के बाकी दिनों में भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बन सकते हैं। यह अंधेरा दरअसल हमारी आत्मा का वह उजाला है जो हमें प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने, पानी बचाने और हरियाली बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज जलवायु परिवर्तन कोई किताबी शब्द नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। कहीं बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों का पिघलना और समंदर का बढ़ता स्तर हमें लगातार चेतावनी दे रहा है। अर्थ ऑवर किसी चेतावनी का एक स्कारात्मक आंदोलन में बदलने का जरिया है। यह वह समय है जब हम अपनी मशीनी दुनिया से कटकर अपनों के साथ बैठ सकते हैं और उन खामोशी को महसूस कर सकते हैं जिसे हम दिनभर के शोर-शराबे में अनसुना कर देते हैं।

आज का इतिहास

- 1866 पहली एम्बुलेंस को सेवा के लिए तैयार किया गया।
- 1891 पहला दुनिया भारोत्तोलन चैम्पियनशिप आयोजित किया गया।
- 1910 मार्टिनुस, फ्रांस के पास, फ्रांसीसी एविएटर हेनरी फाबरे के फैबरहाइड्रावियन अपनी ताकत के तहत पानी से दूर जाने वाला पहला समुद्री जहाज बन गया।
- 1920 मिडवेस्टर्न और सर्दन यूनाइटिड स्टेट्स में 37 बवंडर का प्रकोप होने से 380 से ज्यादा लोग मारे गए।
- 1922 अमेरिकी आविष्कारक ब्रेडली ए. फिस्क्रे ने माइक्रोफिल्म पटन यंत्र का पेटेंट कराया।
- 1930 तुर्की ने अपने सबसे बड़े शहर कांस्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया।
- 1933 इंपीरियल एयरवेज के बाइप्लेन सिटी ऑफ लिबरपूल में सवार एक यात्री ने बोर्ड में आग लगा दी, जिससे वह मध्य हवा में टूट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
- 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के कब्जे वाले फ्रांस में, ब्रिटिश नौसैनिक बल ने सेंट-नाज़ायर के प्रमुख बंदरगाह को असफल रूप से निष्क्रिय कर दिया।
- 1949 संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव जेम्स फोरेस्टल ने अचानक हस्तीफा दिया
- 1959 चीन ने तिब्बत की सरकार भंग की और पांचेन लामा को पदासीन किया।
- 1962 सीरिया में सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति नाजिम अल-कुदूसी देश छोड़कर भागे।
- 1965 डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए एलाबामा की राजधानी मॉंटगुमरी में 25 हजार लोगों के साथ मार्च निकाला।
- 1981 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इंडोनेशियाई आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण कर लिया।
- 1996 यूयॉर्क शहर के वाल्टर केर श्रेटन में कार्यक्रम सात गिटार खुला था।
- 1996 केटी बीम, जो 17 साल की थी, ओकलाहोमा ने अमेरिका की 35 वीं मिस टैनएज को जन्म दिया।
- 1999 विनस विलियम्स ने बहन सेरेने को हराकर लिप्टन कप जीता। 115 साल में यह पहला मौका आया।
- 1999 सर्वियाई पुलिस और विशेष बलों ने सेंट्रलकोसोवो के ड्रेनिका क्षेत्र में इजुबिका के गाँव में कम से कम 89 कोसोवो अलबानियों को मार डाला।
- 2005 रिक्टर पैमाने पर 8.7 की तीव्रता वाला सुनारतन भूकंप 1965 के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था।

अभिनय आकाश

भारत में जितने भी ऐसे एनजीओ चल रही हैं या जो सो कॉलड सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं जो विदेशों से पैसा लेती हैं, उन सब पर अब सरकार का बड़ा प्रहार होने जा रहा है। कैसे ? सारी रिपोर्ट देनी होगी फंडिंग की। एक-एक चीज का ब्यौरा देना होगा। इसीलिए एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। विधेयक में एफसीआरए लाइसेंस रद होने या समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अनुदान से बनाई गई संपत्तियों जब्त करने और उनको देख-रेख के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर नई अर्थांरिटी बनाने का प्रविधान है।

विपक्ष की ओर विधेयक को खतरनाक बताकर पेश करने का विरोध का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह वास्तव में उन लोगों के लिए खतरनाक है जो विदेशी योगदान का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण के लिए या व्यक्तिगत लाभ करते हैं।

एफसीआरए का फुल फॉर्म Foreign Contribution Regulation Act जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम कहा जाता है। विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, इसे 2010 में संशोधित किया गया था जब विदेशी दान को विनियमित करने के लिए कई नए उपायों को अपनाया गया था। एफसीआरए उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी चंदा प्राप्त करना चाहते हैं। इन संस्थाओं के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। शुरुआत में यह पंजीकरण पांच वर्षों के लिए होता है, जिसे सभी मानदंडों को पूरा करने पर रिन्यू करवाए जाने का प्रावधान है।

समय समय पर भारत सरकार ने देश में विदेशी सहायता के प्रवाह को कंट्रोल और नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। सबसे पहले 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने घरेलू राजनीति में विदेशी भागीदारी को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम को पारित किया था। 2010 में, विदेशी निवेश पर कुछ अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। 2015



में, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के एक साल बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए फोर्ड फाउंडेशन सहित कुछ प्रमुख धार्मिक समूहों पर प्रतिबंधों को कड़ा दिया। पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने फिर से इस कानून में संशोधन लाकर विदेशों से मिल रहे चंदे को और कड़ा कर दिया।

कानून में हो रहे इन बदलावों को आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं—

1. पहला बड़ा बदलाव सजा और जांच के तरीके में है। सरकार ने इस कानून के उल्लंघन पर होने वाली जेल की सजा को 5 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया है। इसके पीछे सोच यह है कि छोटी गलतियों पर अपराधी बनाने के बजाय संस्थाओं को नियम सुधारने का मौका दिया जाए। साथ ही, अब किसी भी संस्था के खिलाफ पुलिस सीधे जांच शुरू नहीं कर पाएगी; इसके लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जानकारों का मानना है कि इससे अधिकारियों की मनमानी कम होगी और समाजसेवी संस्थाएं बिना डरे काम कर सकेंगी।

2. दूसरा बदलाव संस्था चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी से जुड़ा है। अब सरकार ने मुख्य पदाधिकारियों का दायरा बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब संस्था के केवल बड़े अफसरों ही नहीं, बल्कि ट्रस्टी, पार्टनर और कमिटी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों पर भी कड़ी नजर रहेगी। अगर इनमें से किसी का भी पिछला रिकॉर्ड खराब है या उन पर कोई केस चल रहा है, तो उस संस्था को विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस नहीं

मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो, सरकार ने सजा तो कम कर दी है, लेकिन संस्था चलाने वाले लोगों की ईमानदारी की जांच का घेरा और चौड़ा कर दिया है।

विदेशी फंडिंग सिस्टम पर नियंत्रण और सख्त होगा। विदेशी धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए अलग से अर्थांरिटी बनेगी। एनजीओ का

रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ तो सारी संपत्ति अर्थांरिटी के पास चली जाएगी। एनजीओ का लाइसेंस रद्द हुआ तब भी सारी संपत्ति अर्थांरिटी के पास जाएगी। विदेशी फंड से जुड़ी किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई संस्था सस्पेंड है तब भी वह संपत्ति का लेनदेन नहीं कर सकती। गड़बड़ी पर पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। फॉरेन फंड्स की जांच के लिए केंद्र की अनुमति लेनी होगी और कोई भी गड़बड़ी एनजीओ में अगर पाई जाती है तो अर्थांरिटी के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 2018 में राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक लाइन कहा कि जो विदेशों से आप पैसा प्राप्त करते हैं ना वो एसबीआई के अकाउंट में लीजिए। नई दिल्ली वाला एसबीआई का अकाउंट पता चला कि 506000 एनजीओ बंद हो गए। आपका एसबीआई अकाउंट है जो फॉरेन फंडिंग है सिर्फ वहां से ले लीजिए। वहीं मंगवा लीजिए। बंद हो गए। सरकार ने कहा कि यह बंद क्यों हो गए ? जितना पैसा आप विदेश से प्राप्त करते हैं वो तो समाज सेवा के नाम पर आप प्राप्त करते हैं। तो उसका सिर्फ आप 30% प्रशासनिक खर्चें में जैसे कि अपने एनजीओ के कर्मचारियों को सैलारी देना हो गया। अगर कहीं ऑफिस खोल के रखा है तो उसका रेंट देना हो गया। वो 30% यहां खर्च कीजिए। लेकिन 70% तो उस काम के लिए खर्च कीजिएगा ना जिसके लिए पैसा प्राप्त किया है। तो उन्होंने कहा एक कैप लगा दिया कि 30% ही प्रशासनिक खर्चें कर सकते हैं। बाकी आपको

अंतहीन बारूदी जंग और भारत का भविष्य-पथ

राजकिशोर

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर इस बार केवल कुटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं था। उनके शब्दों में स्पष्टता और चेतावनी थी। यह स्वर केवल युद्ध की विभीषिका नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक संकट की गहरी पदचाप सुना रहा था। जब देश का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान स्थिति की तुलना कोविड जैसे अभूतपूर्व दौर से करे तो समझ लेना चाहिए कि मामला केवल दो देशों की सहृदयी जंग का नहीं है। यह भारत के ऊर्जा गलियारों,साइबर दीवारों और करोड़ों भारतीयों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। प्रधानमंत्री ने देश को तैयार रहने का आह्वान किया है। यह एक ऐसी रणनीतिक युद्ध की रणभेरी है जिसमें जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि संयम, दूरदर्शिता और आंतरिक मजबूती से तय होगी। पश्चिम एशिया की यह आग अब केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहने वाली। यह भारत की उस वैश्विक महत्वाकांक्षा की भी परीक्षा है जिसे हमने पिछले दशक में बड़ी मेहनत से संवारा है।

प्रधानमंत्री ने सदन में सबसे बड़े खतरे के रूप में इस संकट के लंबा खिंचने की ओर इशारा किया। यह कोई तात्कालिक टकराव नहीं, बल्कि एक अंतहीन लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। यह संघर्ष पूरी विश्व व्यवस्था को बदलकर खेगा। भारत के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमारी विकास की रफ्तार ऊर्जा की अटूट आपूर्ति पर टिकी है। हमने अपनी तैयारियों को विस्तार देते हुए अब 27 के बजाय इकतालीस 41 देशों से कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भूगोल की कड़वी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा जिस संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है, वहां युद्ध के बादलों ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारत साढ़े पांच दशक के सबसे बड़े तेल भंडारण और रिफाइनिंग क्षमता के विस्तार पर काम कर रहा है। इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे संवेदनशील मुहाने पर पैदा हुई कोई भी बाधा हमारी ऊर्जा सुरक्षा को संकट में डाल



सकती है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने हमें पहले ही उर्वरक और यूरिया का बड़ा घाटा दिया था। अब यह मौजूदा संघर्ष हमारी आर्थिक धमनियों को ही काटने की क्षमता रखता है।

इस युद्ध ने भारत के उस महत्वाकांक्षी गलियारे पर भी संकट के साये डाल दिए हैं, जिसे हम एक नए विश्व व्यापार मार्ग के रूप में देख रहे थे। भारत से यूरोप तक जाने वाला वह रास्ता अब मिसाइलों की जद में है। इजरायल के बंदरगाहों पर मंडराता खतरा और समुद्री परिवहन की दरों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने पूरे मार्ग को फिलहाल जोखिमों से भर दिया है। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा फायदा उन शक्तियों को मिल सकता है जो अपनी विस्तारवादी आर्थिक नीतियों के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में भारत को अपने उन समझौतों पर नए सिरे से गौर करना होगा जो मध्य पूर्व की शांति की बुनियाद पर टिके थे। अब समय उन द्विपक्षीय समुद्री रास्तों और विकल्पों को तेजी से जमीन पर उतारने का है जो हमें किसी एक क्षेत्र की अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील बना सकें।

प्रधानमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। यह एक और अदृश्य लेकिन अत्यंत

घातक मोर्चे की ओर इशारा है जिसे हम साइबर युद्ध कहेंगे। भारत अपनी सूचना प्रणाली और डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहा है। युद्ध के इस दौर में जब उन देशों की कंपनियां खुद संकट में हों, तब भारत की बिजली ग्रिड और परमाणु संयंत्रों जैसे संवेदनशील ठिकानों के

लिए सुरक्षा संबंधी सूचनाएं समय पर मिलना कठिन हो सकता है। विदेशी सॉफ्टवेयरों के जरिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की धमकियां आज डार्क वेब और गुप्त नेटवर्क में तैर रही हैं। ये धमकियां हमें स्वदेशी साइबर कवच की अनिवार्यता समझा रही हैं। प्रधानमंत्री का बाहरी शक्तियों की सक्रियता के प्रति आगाह करना यह संकेत देता है कि भारत अब किसी के भरोसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकता।

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता उन करोड़ों भारतीयों को लेकर है जो खाड़ी देशों में रहकर देश का विदेशी मुद्रा भंडार भरते रहे हैं। अब तक देशक पौने चार लाख भारतीय वापस लौट चुके हैं। यह पलायन केवल एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव है। विदेशों से आने वाले धन में भारी गिरावट की आशंका हमारे रियल एस्टेट और बैंकिंग क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। केरल और पंजाब जैसे राज्यों के गांवों में जो आर्थिक रौनक खाड़ी के निवेश से आती थी, वहां अब एक अनजाना डर और सन्नदा पसरने लगा है। लौट रहे इन कुशल और अर्थ-कुशल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर एक राष्ट्रीय

योजना बनानी होगी। इनका कौशल बोझ बनने के बजाय हमारी औद्योगिक शक्ति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का सबसे तीखा और समयोचित प्रहार उन तत्वों पर था जो राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर क्षुद्र स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए आपदा में अक्सर तलाशने की फिराक में रहते हैं। जब देश एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा हो, तब कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। यूरिया, गैस और तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का फायदा उठाकर आम आदमी की जेब काटने वालों को सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है। ऐसी शक्तियों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। आपदा के समय घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखना और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने शांत मन से हर चुनौती को स्वीकार करने और हालात का फायदा उठाने वालों को नाकाम करने की बात कही है। यह देशवासियों के लिए एक नैतिक बल की तरह है।

यह संघर्ष कितना लंबा और वीथत्स होगा, इसका अंदाजा फिलहाल किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री का सदन में दिया गया बयान साफ करता है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सजग प्रहरी के रूप में तैयार है। उन्होंने लंबी समस्या चलने की बात कहकर पूरे तंत्र और समाज को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया है। मतलब साफ है कि यह समय केवल सरकार के तैयार होने का नहीं, बल्कि पूरे देश की एकजुटता का है। सबको तैयार रहने की बात कहकर यह भी इशारा कर दिया गया है कि लड़ाई लंबी है और हर स्थिति के लिए देशवासियों को तैयार रहना होगा। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विश्व की इस महाजंग के बीच भारत की विकास यात्रा की गति धीमी न पड़े। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए हमें इस चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकलना होगा।

शांति की चाह में परस्पर शत्रु देशों की आशा भरी निगाहें भारत की ओर

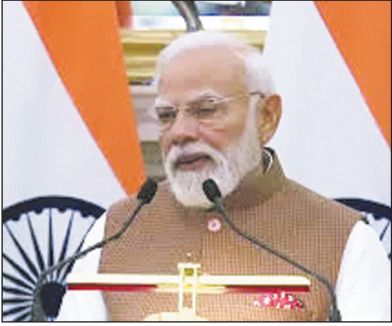
डॉ राघवेंद्र शर्मा

आज का भारत वैश्विक क्षितिज पर एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति उभर रहा है, जिसकी चमक से दुनिया की महाशक्तियाँ भी चकित हैं। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सुझाव देना कि युद्ध विराम और शांति स्थापना के लिए उन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संपर्क साधना चाहिए, केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह बदलते विश्व क्रम की उस हकीकत का प्रमाण है जहाँ भारत अब एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह स्वीकारोति भारत की उस बढ़ती साख को रेखांकित करती है जिसने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को पुनर्परिभाषित कर दिया है।

वर्तमान भारत जिस अवस्था में पहुँच चुका है, वह उसे वैश्विक शांति के लिए दुनिया भर के नेताओं के बीच आशा का एक सशक्त केंद्र बिंदु बनाती है। भारत की यह मान्यता और प्रतिष्ठा केवल हवा-हवाई दावों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस कूटनीतिक सफलताएँ और सामरिक कौशल की गाथाएँ छिपी हैं। दुनिया के सबसे संवेदनशील जल

क्षेत्रों और बंदरगाहों, विशेषकर जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक मार्गों पर जहाँ आज भी युद्ध की विभीषिका के कारण बड़े-बड़े विकसित देशों के तेल वाहक जहाज और मालवाहक पोत बारूदों का शिकार हो रहे हैं या वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं भारत के तिरंगे के साथ चलने वाले तेल वाहक विमान और पोत निर्बांध रूप से अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं। यह दृश्य भारत की उस अदृश्य शक्ति और विश्वसनीयता को दर्शाता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत चुनौती देने का साहस नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि ईरान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और उसके बढ़ते प्रभाव के आगे खुद को असहज और विरोध करने में असमर्थ पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के अपने पुरातन मंत्र को आधुनिक कूटनीति का आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि जहाँ एर और इजरायल जैसा शक्तिशाली और तकनीकी रूप से समृद्ध राष्ट्र भारत की अपना सबसे विश्वसनीय मित्र मानता है, वहीं दूसरी ओर अरब जगत और



ईरान जैसे देशों के साथ भी भारत के संबंध मधुरता और सम्मान के नए पायदान चढ़ रहे हैं।

जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध की ज्वाला भड़की और पूरी दुनिया दो धड़ों में बँट गई, तब केवल भारत ही वह शक्ति था जिसने दोनों पक्षों की आँखों में आँखें डालकर अपने हितों की बात की। हजारों भारतीय नागरिकों और छात्रों के युद्ध क्षेत्र में फंसे होने की खबर ने पूरे देश को चिंतित कर दिया था, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी का ही ओजस्वी व्यक्तित्व और भारत की साख थी कि दोनों युद्धरत देशों ने भारत के आग्रह पर अस्थायी

रूप से युद्ध विराम किया ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। ऑपरेशन गंगा की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि नए भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसा ही दृश्य ईरान में भी देखने को मिला जब अमेरिकी हमलों और अशांति के माहौल के बीच ईरानी सरकार ने भारतीयों की सुरक्षित निकासी में अभूतपूर्व सकारात्मक रुख दिखाया। यह सम्मान किसी डर से नहीं, बल्कि उस विश्वास से उपजा है जो भारत ने अपनी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नीतियों के जरिए वैश्विक मंच पर कमाया है।

आज जब हम वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं, तो एक बहुत ही व्यापक और स्पष्ट तस्वीर उभरती है कि दुनिया के तमाम देश चाहे आपस में कितने ही विरोधाभासों या युद्धों में क्यों न उलझे हों, लेकिन वे भारतीय नागरिकों और भारत सरकार के प्रति अटूट सम्मान का भाव रखते हैं। यह भारतीय कूटनीति की वह विजय है जहाँ हमने बिना किसी गुटबाजी में फंसे, अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ हाथ मिलाया है। घरेलू स्तर पर भले ही राजनीतिक मतभेदों

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की सतर्कता

बिनोद कुमार सिंह

पश्चिम एशिया में बदलते भू- राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत ने जिस संतुलित,सजग और दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, वह न केवल उसकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है,बल्कि नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।हर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी गंभीर स्थिति के बावजूद देश में पेट्रोल,डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है।यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर समय रहते ठोस और प्रभावी तैयारी कर रखी है।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अंशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर कार्य कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।पेट्रोल और डीजल के स्टॉक भी संतोषजनक स्तर पर बनाए रखे गए हैं।हालाँकि अफवाहों के चलते कुछ स्थानों पर घबराहट में खरीदारी देखने को मिली,लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और जनता को अफवाहों से दूर रहने की आवश्यकता है।परेलू खपत को ध्यान में रखते हुए एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की गई है। साथ ही, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी)आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए भी संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है,ताकि आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।विशेष रूप से होटल,रेस्तरां और सामुदायिक रसोई जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।यह आदेश देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तारो को गुप्त में और ऊर्जा के स्वच्छ एवं सुलभ विकल्प के रूप में पीएनजी को बढ़ावा देगा।इससे न केवल पारंपरिक ईंधनों पर दबाव कम होगा,बल्कि

पर्यावरणीय दृष्टि से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एलपीजी आपूर्ति वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित अवश्य हुई है,लेकिन देश में कहीं भी ‘ड्राई-आउट’ की स्थिति नहीं है। घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों और सेवा क्षेत्रों को राहत मिली है।इसके अतिरिक्त,केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है,ताकि माँग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। हजारों छापों और सैकड़ों गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है।जिला स्तर पर निायानी समितियों और नियंत्रण कक्षों की स्थापना से स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। समुद्री क्षेत्र में भी भारत की सक्रियता उल्लेखनीय है।पश्चिमी फारस की खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से नाविकों और उनके परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है।अब तक सैकड़ों भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है,जो इस दिशा में सरकार के समर्पण को दर्शाती है।विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास चौबीसों घंटे कार्यरत हैं और जरूरतमंद नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक लाखों भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट चुके हैं।विशेष उड़ानों और वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से यह अभियान लगातार जारी है। इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता का स्पष्ट संदेश दिया है।

काश! केजरीवाल बाकी नेताओं से अलग होते

अभिलाष खांडेकर

यह सर्वविदित है कि राजनेता गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। यह केवल अपना दल और विचारधारा बदलने की बात नहीं है, बल्कि सत्ता हथियाने के बाद खुद को अंदर-बाहर से पूरी तरह से बदल लेने की है। इस कड़ी में नवीनतम नाम अविंद केजरीवाल का है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने निराशा से घिरे भारतीयों के बीच वैकल्पिक राजनीति की नई उम्मीद जगाई थी। परंतु ‘कैग’ की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वे अंदर से बदल गए थे और उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं को अन्य चीजों से ऊपर रखा। कैग उस शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा है जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा हुई थी; वह ‘शीश महल’ की बात बता रहा है।

वर्ष 2012-13 में केजरीवाल राष्ट्रीय नायक बन गए थे क्योंकि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। ‘इंडिया ऑगेंस्ट करप्शन’ के शक्तिशाली अभियान ने निराश भारतीयों को एकजुट कर दिया था। शिक्षित युवा बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हुए क्योंकि उन्हें अंधकारमय सूरंग के अंत में कोई रोशनी दिखने लगी थी। जाहिर है, वे अना हजारे की बातों पर विश्वास करते थे। भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल की सादगी ने उन्हें प्रभावित किया था।

उन्होंने उस नए दल को एकजुट होकर मतदान किया जिसका नाम आम आदमी की वास्तविक चिंताओं से मेल खाता था। उसने भविष्य के लिए आशा जगाई थी। आम आदमी पार्टी (आप) भारत के राजनीतिक रूप से धुंधले क्षितिज पर चमकता सितारा बनी थी।

लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जल्द ही एक और भारतीय राजनीतिक दल बनकर रह गई। उन्होंने अपने सभी महत्वपूर्ण साथियों को दक्किनार कर दिया, जिन्हें वे अपने लिए खतरा मानते थे। लेकिन लगभग तीन कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी असलियत सामने आ ही गई। दिल्ली विधानसभा चुनावों के पिछले नतीजों से साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले एक नाकाबिल विकल्प थी।

‘कैग’ की नवीनतम रिपोर्ट (2022) के अनुसार, केजरीवाल ने नई दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास के सौंदर्यकरण और नवीनीकरण पर



33.6 करोड़ रुपए खर्च किए। यह राशि स्वीकृत राशि से 342 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप भले ही राजनीतिक हों, लेकिन ‘शीश महल’ राजनीतिक नहीं है। खर्च की गई राशि देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। यह उस दौर में बहुत कम है जब बड़े राज्य और उनके नेता अपने ऊपर कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं और सरकारी खजाने में रोजाना छेद कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात पर होता है कि राजनेता विलासितापूर्ण सुख-सुविधाओं का आनंद लेने के लिए सरकारी खजाने पर द्र्ट पड़ते हैं। भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर दो आलीशान बंगले आवंटित करवाए और केजरीवाल से कहीं अधिक खर्च किया। इनमें से एक मजबूत और अच्छी तरह से निर्मित सरकारी बंगला जर्जर घोषित कर दिया गया, नगर निगम अधिकारियों ने राजनैतिक दबाव में आकर उसे ध्वस्त कर दिया। जल्द ही वहां एक नया बंगला बनाया जा रहा है। एक अन्य मुख्यमंत्री ने अपने सुंदर और विशाल बंगले की सीमा को बढ़ाकर आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़क तक पहुंचा दिया।

करदाताओं के पैसे से बंगले के अंदर निर्माण और नवीनीकरण का काम जारी है और कोई भी मौजूदा नियम इसे रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों को लगता है कि वे जीवनभर वहीं रहेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेता जनता के धन का बेहिसाब दुरुपयोग अपनी निजी सुख-सुविधाओं पर करते नजर आ रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। भारत में अनगिनत उदाहरण हैं जहां

राजनीतिक नेता चुनाव जीतने के बाद हर तरह के लाभ तलाशने में जुट जाते हैं और उस जनता की अनदेखी करते हैं जिसने उन्हें सत्ता में पहुंचाया है। अगर किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा देश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का ठीक से ऑडिट किया जाए, तो वे स्वयं पर बेहिसाब खर्च के मामले में दोषी पाए जाएंगे, जिनमें भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हैं। मध्यप्रदेश के एक मंत्री के पास हूटर लगी छह सरकारी गाड़ियां हैं और उनके आवास-सजावट आदि पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं।

फिर भी, मुझे लगता है कि केजरीवाल दूसरों से ज्यादा दोषी हैं। कांग्रेस नेता सार्वजनिक जीवन में सादगी या ईमानदारी की बात कम ही करते थे, लेकिन केजरीवाल बार-बार करते थे। तब उन्हें ऐसे आलीशान घर की क्या जरूरत थी? चुनाव से पहले तो वे आम आदमी थे। आखिर उनमें इतना बदलाव क्यों आया?

उनकी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित ने उसी बंगले में 15 वर्षों तक सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा उसकी मरम्मत करवाकर नया रंग-रोगन करवा सकते थे। लेकिन 33 करोड़ रुपए? माफ कीजिए, यह सादगी नहीं थी। भाजपा द्वारा ‘शीश महल’ कहे जाने वाले इस बंगले पर खुलकर जनता का पैसा खर्च किया गया। वैकल्पिक राजनीतिज्ञ बनने के अपने वादों को देखते हुए, मुख्यमंत्री को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जीवन में एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, लेकिन वे असफल रहे।

मैंने भाजपा नेताओं का सादगी भरा जीवन देखा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके शिष्य कैलाश जोशी मप्र के मुख्यमंत्री के रूप में बेहद सरल रहे थे। लेकिन वह भाजपा आज की दिखावटी भाजपा से बिल्कुल अलग थी। उधर, ज्योति बसु को छोड़कर वामपंथी दलों के सभी नेता भी सादगीपूर्ण रहे हैं। त्रिपुरा के माणिक सरकार को भी जरा याद कीजिए।

केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद खुद के बारे में कहा था कि वे भ्रष्ट नहीं हैं। फिर भी इतिहास में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारत में एक तीसरी व ईमानदार शक्ति बनने की जरूरत के समय लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। यही उनका सबसे बड़ा अपराध है!

कांतिलाल मांडे

गुजरात विधानसभा में पारित ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक, 2026’ केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय समाज की संरचना में एक व्यापक बदलाव का संकेत है। यह विधेयक उस लंबे विमर्श का परिणाम है, जो दशकों से समान नागरिक कानून की अवधारणा को लेकर देश में चलता रहा है। अब गुजरात ने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हों, चाहे उनका धर्म, आस्था या परंपरा कुछ भी हो। लंबे समय से भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते रहे हैं, जिनमें विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम भिन्न-भिन्न रहे हैं। इससे कई बार सामाजिक और कानूनी असमानताएं उत्पन्न होती रही हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में। यूसीसी इन असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक कानून के रूप में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्तिगत मामलों में भी राज्य एक समान नियम लागू करेगा, जिससे कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन में एकरूपता आएगी। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के लिए समान प्रक्रिया, और उत्तराधिकार में पुत्र-पुत्री को समान अधिकार—ये सभी प्रावधान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कानून अब व्यक्ति की धार्मिक पहचान के बजाय उसकी नागरिक पहचान को प्राथमिकता देगा। विधेयक में लिव-इन संबंधों

चुनौती, भारत की भूमिका अग्रणी रहती है। भारत की यह नई सामर्थ्य प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करती है। आज का भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में गर्व से अपना सिर उठाकर कह सकता है कि वह उस महान देश का हिस्सा है जो युद्ध को खत्म करने की क्षमता रखता है और जो मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है।

यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक नेतृत्व का वह अद्भुत संगम है जिसने हमें वैश्विक राजनीति के ध्रुव तार के रूप में स्थापित कर दिया है। इस महान राष्ट्र की बढ़ती शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए है। वास्तव में, यह भारत का स्वर्ण युग है जहाँ हमारी सीमाओं के बाहर हमारा मान बढ़ा है और सीमाओं के भीतर देश का स्वाभिमान अपनी चरम सीमा पर है। भारत का यह बढ़ता कद और प्रधानमंत्री मोदी का यशस्वी नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत स्थापित कर रहा है, जिसमें भारत फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला सिरमोर राष्ट्र कहलाएगा।

धर्म और जाति को लेकर आए सुप्रीम आदेश



को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सुचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जहां कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदूरदर्शिता वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है।

जहां तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपांतरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूँकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दबाव बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठया गया निर्णायक कदम है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार दलित/ओबीसी हिंदुओं की एकजुटता व समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

हालाँकि देश में जाति से जुड़ा सवाल बहुत टेढ़ा और जटिल है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि क्या धर्म बदलने पर से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? गांहे बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें दलित या ओबीसी समुदाय के लोगों

को दूसरा धर्म अपनाने के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले साल मार्च में ही तमिलनाडु के कुछ ईसाई परिवारों, जो पहले दलित थे, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। यहां तक कि कब्रिस्तान में उनके लोगों के शवों को दफनाने के लिए भी अलग जगह है।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के फैसले का आधार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है। जिसका क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही एससी श्रेणी में आ सकते हैं। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू है। एक, जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ छोड़ दिए हों। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाले फायदे लेते रहना संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास इस तरह की कई शिकायतें है और उसने पिछले साल देशभर में जांच भी शुरू की थी। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि संविधान के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि जाति और धर्म का दुरुपयोग होने की चिंता शुरू से ही न्यायिक विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। लिहाजा ब्रेक के बाद न्यायदेश मिलते रहते हैं।

इंद्रा साहनी केस (1992) मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण पर केंद्रित था, लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले (धर्म परिवर्तन पर स्ट्र दर्जा समाप्ति) से इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों आरक्षण को जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने के सिद्धांत साझा करते हैं। इंद्रा साहनी का सार- इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण मान्य किया, लेकिन 50% कुल सीमा तय की और स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार धर्म या जाति अकेला नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर बहिष्कार और पिछड़ापन के सामाजिक-शैक्षिक मापदंड निर्धारित किए गए। हालिया फैसले से संबंध: 2026 के एससी/एसटी फैसले में संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला दिया गया, जो इंद्रा साहनी के सिद्धांतों से मेल खाता है कि आरक्षण धर्म पर आधारित नहीं।

समान नागरिक संहिता का गुजरात मॉडल

को भी कानूनी दायरे में लाया गया है, जो आधुनिक समाज की बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करने का संकेत है। ऐसे संबंधों का एक महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की स्थिति में कानूनी संरक्षण उपलब्ध होगा। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अनौपचारिक संबंधों में अक्सर महिलाएं कानूनी सुरक्षा से वंचित रह जाती थीं। यूसीसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब किसी भी विवाह को तभी वैध माना जाएगा, जब दोनों पक्षों में से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी न हो। यह प्रावधान न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के इसका अप्रत्यक्ष गए तलाक को मान्यता नहीं दी जाएगी, जिससे मनमाने और एकतरफा निर्णयों पर रोक लगेगी। हालांकि यह कानून व्यापक रूप से लागू किया गया है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यह निर्णय उनकी पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार ने समानता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। गुह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले व्यापक जनपरामर्श किया गया, जिसमें लगभग 20 लाख सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश सुझाव इस कानून के समर्थन में थे, जो यह दर्शाता है कि समाज में एक समान कानून की आवश्यकता को लेकर व्यापक सहमति बन रही है। इस विधेयक के निर्माण में रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया है।



सिनेमा में बढ़ती चाहिए महिलाओं की भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंगना रनौत का बयान

नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो चुका है, जो 30 मार्च तक चलेगा। फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में कंगना रनौत, हेमा मालिनी, विक्की कौशल, सान्या मालहोत्रा, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनुपम खेर और लारैन गॉटलिब जैसे स्टार्स को देखा गया। समारोह में पहुंची भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो हम उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

धुरंधर का रहा मार्च, अप्रैल में ये फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार



मार्च में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और अच्छी कमाई कर रही है। आदित्य धर की फिल्म का विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी जलवा है। स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड पर विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। अब अप्रैल में भी बॉलीवुड दर्शकों के लिए कई बड़ी और रोचक फिल्में लेकर आ रहा है। अप्रैल में हर जॉनर की फिल्म रिलीज होगी। इन फिल्मों में एक्शन, रोमांस, हॉरर-कॉमेडी और पीरियड-ड्रामा के साथ भरपूर मनोरंजन दर्शकों को मिलेगा। अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'आवारापन 2' के साथ ही सलमान खान, अक्षय कुमार की फिल्मों का भी नाम शामिल है। 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में 3 अप्रैल को रिलीज होगी। साल 2007 की हिट फिल्म 'आवारापन' के सीकल में इमरान हाशमी मुख्य

शुरुआत में दिन-रात करता था लगातार काम, अब समझ आई जिंदगी में संतुलन की अहमियत : हितेन तेजवानी

टीवी इंडस्ट्री की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। कलाकारों को लगातार शूटिंग करनी पड़ती है और कई बार दिन-रात काम करना पड़ता है। इस कड़ी में टीवी अभिनेता हितेन तेजवानी ने अपने करियर के शुरुआती सालों की मेहनत और आज के बदले हुए नजरिए के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब वह 24 घंटे में करीब 18 से 19 घंटे तक काम किया करते थे। हितेन तेजवानी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा, "टीवी इंडस्ट्री में शुरुआत के समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर ही रहता था। उस समय मैं लगातार शूटिंग में बिजी रहता था, नींद के लिए बहुत कम समय मिल पाता था और बाकी किसी चीज के बारे में सोचने का समय भी नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 24 घंटे में 18 से 19 घंटे तक लगातार काम करता रहता था और मुश्किल से कुछ घंटे ही सो पाता था।" हितेन ने कहा, "उस समय मेरे अंदर काम को लेकर जबरदस्त जुनून था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं अपने काम को और बेहतर कैसे करूँ। वही



मेहनत और लगातार काम करने का जज्बा मुझे आज इस मुकाम तक लेकर आया है। अगर मैंने उस समय इतनी मेहनत नहीं की होती, तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता और इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक भी नहीं पाता।" अभिनेता ने कहा, "समय के साथ इंसान का नजरिया बदलता है। दो दशक से ज्यादा समय तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब मुझे यह महसूस होता है कि जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद एक ऐसा दिन आता है, जब इंसान को संतुलन की अहमियत समझ आने लगती है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि काम के घंटे सीमित हों, ताकि मुझे आराम और परिवार के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके।" हितेन ने कहा, "आज मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखता हूँ कि जीवन के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज न करूँ। परिवार के साथ समय बिताऊँ, आराम करूँ और मानसिक शांति बनाए रखूँ, क्योंकि यह उतना ही जरूरी है, जितना कि पेशेवर सफलता हासिल करना।"

सेलिना जेटली को मिला प्रीति जिंटा का साथ, ईद पर दी नई हिम्मत

बॉलीवुड की 'नो एंट्री' फेम एक्ट्रेस सेलिना जेटली इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। उनका पति पीटर हाग से तलाक का केस चल रहा है। वे अपने तीनों बच्चों से भी बहुत दूर हैं। अभिनेत्री का भाई भी अब्बू धाबी की जेल में बंद है। इन मुश्किल हालातों ने अभिनेत्री को तोड़कर रख दिया है, लेकिन इस ईद पर उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सेलिना जेटली ने अब बहुत प्यारा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो ट्रेडिशनल आउटफिट में दिख रही हैं और गहनों से लदी हैं। अभिनेत्री को काफी समय बाद ऐसे अवतार में देखा गया है। खुद को यूँ सजा और तैयार करके सेलिना का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें अच्छा फील कराया प्रीति जिंटा ने, जिन्होंने उन्हें तैयार होने के लिए मोटिवेट किया। अपनी प्यारी फोटोज शेयर कर सेलिना ने प्रीति जिंटा का दिल से शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा, एक अलग तरह की ईद, जिसने मुझे खुद से फिर से जोड़ा। बहुत लंबे समय बाद, मैंने ट्रैकसूट और वर्कआउट कपड़ों के अलावा कुछ और पहना। काफी समय बाद, यह मेरा पहला कदम था, पूरी तरह सज-धज कर बाहर आना। मेरी दोस्त प्रीति जिंटा ने मुझे तैयार होने और खुद के लिए बाहर आने के लिए प्रेरित किया। सेलिना के मुताबिक खुद को तैयार करके वह आत्मनिर्भर और शक्ति से भरा महसूस



कर रही हैं। पहले उन्होंने पेशानियों में खुद को इतना घोल लिया कि खुद को पूरी तरह भूल गईं और सजना-संवरना छोड़ दिया था। अब तैयार होकर उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके अंदर एक अलग शक्ति है और वो हर चीज की हकदार हैं, चाहे बात कपड़ों की हो या फिर संजने-संवरने की। उन्होंने आगे लिखा, जो भी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, खुद के लिए समय निकालें। सज-धज कर तैयार हों, भले ही सिर्फ अपने लिए ही सही। क्योंकि कभी-कभी, एक छोटा सा प्रयास ही आपको फिर से पहले जैसा महसूस कराने की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि मैं खुद को भूल चुकी थी।

विजय देवरकोंडा ने शादी को खास बनाने वाली तीन महिलाओं को कहा थैंक्स

ज्वेलरी को बताया सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत

उदयपुर में 26 फरवरी को शादी करने के बाद से ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सोशल मीडिया का सबसे चर्चित कपल बन चुके हैं। इस बीच अभिनेता ने अपनी शादी में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाली तीन महिलाओं को याद किया है। विजय देवरकोंडा ने शादी के एक महीने बाद शादी की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं को स्पेशल थैंक्स कहा है, जिसमें उनकी वेडिंग प्लेनर, करीबी दोस्त ऐश्वर्या और उन्हें गहनों से सजाने वाली डिजाइनर शामिल हैं। अभिनेता ने तीनों को लेकर बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं और शादी को यादगार बनाने का श्रेय भी दिया। विजय देवरकोंडा ने पहले अपनी दोस्त ऐश्वर्या को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, बिना कहे ही वो शादी का फैसला करने के पल से ही मेरे साथ थी, ताकि मैं और रुशी खूब मजे कर सकें। घूमने-फिरने से लेकर जगह चुनने, खाना चखने, खूब मस्ती करने, कपड़े खरीदने से लेकर गहने, निमंत्रण पत्र, सजावट, यात्रा-हर काम में वो हम दोनों के साथ थीं। अभिनेता ने अपनी दोस्त को शुक्रिया कहने के लिए भी अनोखा तरीका निकाला। अभिनेता ने तय किया कि वो रिसेप्शन में जो भी पहनेंगे वो सब उनकी दोस्त के होंगे। उन्होंने रिसेप्शन के दिल ऐश्वर्या की पायल को गले का हार और कंगन बनाकर पहना था, ताकि वे उन्हें हमेशा याद रख सकें। विजय देवरकोंडा ने ज्वेलरी डिजाइनर अर्पिता और वेडिंग प्लानर प्रिया का भी दिल से धन्यवाद दिया। अभिनेता के मुताबिक दोनों के बिना यह शादी इतने अच्छे तरीके से हो पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने वेडिंग प्लानर प्रिया से कहा है कि फैमिली में भविष्य में होने वाले सभी फंक्शन वहीं करेंगी। देवरकोंडा ने ज्वेलरी डिजाइनर अर्पिता की भी तारीफ की, क्योंकि अर्पिता ने इन ज्वेलरी डिजाइनों को तराशा जो अभिनेता के दिमाग में थे। उन्होंने लिखा, मैंने उनसे कभी भी 'असंभव' शब्द नहीं सुना-मैंने उनसे वो चीजें मांगी जो मेरे दिमाग में थीं और जिन्हें कोई बना भी नहीं रहा था और उन्होंने सबसे खूबसूरत केक बनाए, जो मेरे सपनों से भी कहीं ज्यादा कलात्मक थे।



जसलीन कौर के किरदार में पंवी पंधेव का जादू, छोटी सी भूमिका में छोड़ी गहरी छाप

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने साल 2025 में रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, तो वहीं दूसरे पार्ट ने रिलीज होते ही हर किसी को चौंका दिया। धुरंधर में जहां सारा ने डेब्यू कर हर किसी को दीवाना बना दिया था, तो 'धुरंधर: द रिवेंज' में पंजाबी सिंगर और अभिनेत्री परी पंधेव ने अपनी सादगी से हर किसी के दिलों को जीता है। फिल्म में परी का छोटा-सा लेकिन प्रभावशाली रोल रहा है। अभिनेत्री ने फिल्म में जसकिरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) की बहन जसलीन कौर रंगी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में परी का किरदार बहुत भावुक और असरदार रहा और उनकी एक्टिंग ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने किरदार को इतनी गहराई दी, जिससे जसकीरत की शुरुआती जिंदगी अच्छे से दिखाई गई। फिल्म में पंजाब का रंग भी साफ झलकता है। रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए परी का यह डेब्यू काफी प्रभावशाली रहा है। वह 2026 की नई उभरती प्रतिभाओं में शुमार हो गई हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सेट से कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, जब आदित्य धर सर की टीम से 'धुरंधर' के लिए फोन आया, तो सबसे पहले पूछा गया कि आपके लिए कितनी गाड़ियां भेजें और कहां भेजें? उस पल सब कुछ सपना लग रहा था। उन्होंने लिखा, उस दौरान मैं अपने मेंटर और भाई बंटी बेंस के साथ बैठी थी और हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम इतने उत्साहित थे कि गाड़ी का इंतजार करने की बजाय अपनी कार में बैठकर सीधे शूटिंग लोकेशन के लिए निकल पड़े। उस सफर के हर पल में शुक्रिया, सपने और खुशी भरी हुई थी। उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए लिखा, कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। वे यह एहसास दिलाते हैं कि आप वाकई उसी के लिए बने हैं। उस दिन मुझे लगा कि कुछ बहुत खूबसूरत शुरू होने वाला है। ऐसे पलों के लिए हमेशा आभारी रहूंगा।



भारत में लॉकडाउन की आशंकाएं महज अफवाह : हरदीप पुरी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को साफ किया कि देशव्यापी लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। वहीं, खुदरा दुकानों के पास पर्याप्त स्टॉक है। वे बिना किसी रुकावट के ईंधन वितरित कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुरी ने कहा, वैश्विक स्थिति में लगातार बदलाव हो रहे हैं और हम ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित घटनाक्रमों पर वास्तविक समय के आधार पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हम उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

जी7 की बैठक से अलग कनाडा के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर

पेरिस। पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके दुनिया पर पड़ रहे असर को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ अहम बैठक की। दोनों नेताओं की यह बैठक जी7 की बैठक से अलग हुई। जयशंकर गुरुवार को त7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे। बैठक के बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने इस वर्ष की शुरुआत में पीएम कार्नी के भारत दौरे पर आगे बढ़ाई गई साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। आनंद ने कहा कि बैठक में व्यापार, पश्चिम एशिया की स्थिति और दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण खनिज, कृषि और शिक्षा पर भी चर्चा हुई। दो दिवसीय जी-7 बैठक में जयशंकर पश्चिम एशिया संकट पर विशेष ध्यान देते हुए इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहे।

सोनिया गांधी की हालत में तेजी से सुधार

नईदिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें एक से दो दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि 79 वर्षीय नेता, जिन्हें 24 मार्च की देर रात भर्ती कराया गया था, की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी की हालत में काफी सुधार है। उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और वे सहज महसूस कर रही हैं। वे चल-फिर रही हैं और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। कुल मिलाकर, उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक-दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल ने इससे पहले बताया था कि गांधी जी को एक गंभीर संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं और उन पर सकारात्मक असर पड़ रहा है।

राज्यसभा चुनाव जीतते ही नीतीश का इस्तीफा तय

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। यह कदम उन्होंने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उठाया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए उनके लिए 14 दिनों के भीतर एक पद छोड़ना अनिवार्य है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों 29 मार्च तक अवकाश पर हैं। सदनों का सत्र 30 मार्च को फिर से शुरू होगा, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उसी दिन विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सूत्रों ने संकेत दिया है कि संवैधानिक आवश्यकता और राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत के बाद की समयसीमा को देखते हुए यह निर्णय लगभग अंतिम है। 16 मार्च को बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।

नेपाल के नए प्रधानमंत्री को मोदी ने भेजा बधाई संदेश

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन को शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने लगभग लगभग छह महीने बाद हुआ है। ओली सरकार को एक युवा पीढ़ी के विरोध प्रदर्शन में हटा दिया गया था। मोदी ने एक्स पर एक संदेश में कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर श्री बालेंद्र शाह को हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे को दर्शाती है। मैं हमारे दोनों देशों की जनता के आपसी फायदे के लिए भारत-नेपाल की दोस्ती और सहयोग को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं।

राम मंदिर के सूर्य तिलक समारोह में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी

अयोध्या में रामलला का हुआ दिव्य सूर्य तिलक

नईदिल्ली। श्रीराम नवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की पूजा-अर्चना की। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह में वचुअल रूप से भाग लिया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। यह लगभग चार मिनट तक चला। विशेष बात यह रही कि तिलक ठीक उसी समय हुआ, जो समय भगवान राम के जन्म का क्षण माना जाता है।



शुक्रवार को अयोध्या में राम नवमी का पवित्र पर्व अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया गया और राम मंदिर में भव्य सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष अयोध्या में भव्य उत्सव का आयोजन राम जन्मभूमि मंदिर में बहुप्रतीक्षित सूर्य तिलक समारोह के साथ किया जा रहा है। राम नवमी पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम लला से प्रार्थना की और अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह का अवलोकन किया। दर्पणों और लेंसों की उन्नत प्रणाली की बदौलत सूर्य की रोशनी गर्भगृह में प्रवेश करती है और कुछ मिनटों के लिए देवता के माथे पर एक चमकदार तिलक बनाती है। यह समारोह दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और परंपरा एवं

आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। भक्तों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर अधिकारियों ने अयोध्या भर में लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, जिससे हजारों भक्त इस क्षण के साक्षी बन सके।

शुक्रवार सुबह अयोध्या में राम नवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, क्योंकि हज़ारों लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए अत्यंत उत्साह के साथ पहुंचे। पवित्र खान करने के बाद, श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए उमड़ पड़े। पूरा शहर गहरी भक्ति के वातावरण में डूबा रहा और जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। भगवान श्री राम की जयंती मना

रहे श्रद्धालुओं में उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की और पुलिस बलों को विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया।

अयोध्या मंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि आज राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में आस्था की लहर दौड़ गई है; हर जगह श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और चारों ओर ‘जय श्री राम’ के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी लगातार मेला मैदान का दौरा कर रहे हैं। वे व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं और स्वयं जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

केरल में भाजपा के लिए एक सीट जीतना भी सपना : वेणुगोपाल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और एआईसीसी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि आगामी केरल विधानसभा चुनावों में गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत निश्चित है, क्योंकि केरल की जनता पिनारयी विजयन के नेतृत्व में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन चाहती है।

मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल ने दावा किया कि दोनों पार्टियों के बीच एक अपवित्र गठबंधन है। उन्होंने कहा कि वे सोचते हैं कि वे एक या दो-तीन सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। केरल विधानसभा में एक सीट जीतना उनके लिए एक सपना ही हो सकता है। वे केरल विधानसभा चुनाव में अपना खता भी नहीं खोल पाएंगे, भले ही वे सीपीएम और भाजपा के इस अपवित्र गठबंधन के साथ कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि केरल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके पास धन बल है, लेकिन केरल एक अलग राज्य है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। जनता का मिजाज कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ के पक्ष में है। आप देख सकते हैं कि केरल का पूरा मिजाज बदलाव के लिए है, सरकार के बदलाव के लिए। हमें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। केरल में पिनारयी सरकार के 10 साल केरल की जनता के लिए सबसे बुरे दौर रहे हैं। लेकिन 9 अप्रैल को केरल की जनता उन्हें दिखाएंगी कि केरल क्या सोच रहा है? कांग्रेस नेताओं का परिवार है। हमारे अपने विचार हैं, शायद थोड़े अलग हों। लेकिन जब भी कोई साझा मुद्दा आता है, हम सब एक साथ होते हैं। अब हर केरलवासी सरकार के बदलाव की मांग कर रहा है।

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने की हमारी अपनी प्रणाली है। चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व केरल की जनता के साथ बैठेगा और वे फैसला करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले हैं और मतगणना 4 मई को होगी।

पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस सांसद का पीएम मोदी पर हमला

बोले- देश को अधर में छोड़ा

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण फैसलों में देरी की आलोचना की है। 27 मार्च को बोलते हुए मसूद ने चेतावनी दी कि देश को अलग-थलग छोड़ दिया गया है और इसके गंभीर परिणाम सभी नागरिकों को प्रभावित करेंगे। स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री देर से जाग रहे हैं। जहाँ समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए थे और जहाँ हम तटस्थ रख अपना रहे थे, वहीं हमें अधर में छोड़ दिया गया है। हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। स्थिति बेहद गंभीर है। लोग चिंतित हैं। व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं। लोग बहुत परेशान हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने और डीजल पर इसे हटाने के बाद यह आलोचना सामने आई है। इसके अतिरिक्त, डीजल निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) लगाया गया है। सरकार की यह कार्रवाई पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता, विशेष रूप से अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के जवाब में है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी कर दी गई है, जो वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति के लगभग पाँचवें हिस्से का परिवहन करने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस संकट से पहले, भारत के तेल आयात का 12-



15% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता था।

हालांकि उत्पाद शुल्क में कटौती का उद्देश्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घाटे का सामना कर रही तेल विपणन कंपनियों को राहत देना है, लेकिन खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक अपरिवर्तित हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश भर में ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने जनता से अफवाहों के बीच घबराहट में खरीदारी न करने की अपील भी की है।

भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता हुई कमजोर : जयराम रमेश

देश में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीते एक दशक में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता कमजोर हुई है। उन्होंने

कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 84रुब से बढ़कर 90रुब हो गई है, जबकि एलपीजी आयात 46रुब से बढ़कर 62% तक पहुंच गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस गैस का वादा किया गया था, वह अब तक सिर्फ वादा ही बनी हुई है।

रमेश ने प्राकृतिक गैस के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए 2005 में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन में बड़े गैस भंडार की खोज के दावे का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में 2011 से 2016 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में इसे 20,000 करोड़ रुपये का घोटाळा बताया गया, जिसे बाद में ओएनजीसी में विलय कर छिपाया गया।

इधर, पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों पर लंबी कतारों की खबरों के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए किसी भी तरह की कमी से इनकार किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में करीब 60 दिनों का कच्चा तेल का भंडार उपलब्ध है और एक महीने की एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित की गई है।

मंत्रालय ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि देशभर के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक है और कहीं भी पेट्रोल-डीजल की राशनिंग नहीं हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने भी सप्लाई सामान्य रहने का दावा किया है। वहीं, विश्वभू ने संसद परिसर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

स्टेल प्रमुख समाचार

आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच आज

बेंगलुरु। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) 28 मार्च, शनिवार से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में

अपना खिताब बचाने के लिए प्रतिबद्ध होगा जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), चेन्नई सुपर किंग्स (एसएसके) और मुंबई इंडियंस अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आईपीएल में अगले दो महीनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कुछ युवा खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी जो अच्छा प्रदर्शन करके अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं रहेंगे। आरसीबी टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में चिन्तास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा और उसका लक्ष्य शानदार शुरुआत करना होगा।

जहां तक मैच का सवाल है तो आरसीबी और सनराइजर्स दोनों के पास गेंदबाजी संसाधनों की कमी है। आरसीबी को जोशा हेज़लवुड और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल के बिना खेलना होगा। दोनों ने 2025 के विजयी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस वर्ष वे अधिकतर मैचों में बाहर रहेंगे। हेज़लवुड ऑस्ट्रेलिया में चोट से उबरकर पूरी तरह फिट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वह बाद में टीम में शामिल हो सकते हैं।

यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे यश दयाल पूरे सत्र से बाहर रहेंगे। आरसीबी को अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्पिनर कर्णाल पंड्या, सुयश शर्मा और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव पर काफी हद तक निर्भर रहना होगा। सनराइजर्स के कप्तान चैट कर्मिस भी शुरुआती चरण में टीम में नहीं होंगे। ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है। लेकिन सनराइजर्स के बैंकअप विकल्प ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगते।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सैंसेक्स 1690 अंक टूटा निफ्टी 22819 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के अंतिम ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार (27 मार्च) को बड़ी गिरावट में बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। इंडेक्स हैवीवेट एडिडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बिकवाली ने भी बाजार को नीचे खींचा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक गिरकर 74,883.79 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 73,534 अंक तक फिसल गया था। अंत में 1690.23 अंक या 2.25 प्रतिशत की गिरावट लेकर 73,583.22 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 पर 23,173.55 खुला। इंट्र-डे ट्रेड में 22,804 अंक के लो लेवल तक गया। अंत में 486.85 अंक या 2.09 प्रतिशत गिरकर 22,819 पर बंद हुआ।

पेट्रोल-डीजल सस्ता! एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 13 रुपये थी, वो अब घटकर 3 रुपये रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 10 रुपये थी, वो अब शून्य हो गई है। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों से जुड़ा रही तेल विपणन कंपनियों, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, को राहत देने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

एलपीजी गैस लेकर गुजरात पहुंचा भारतीय जहाज जग वसंत

नई दिल्ली। ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के चलते कई दिनों से फंसा भारतीय झंडे वाला जहाज जग वसंत भारत पहुंच गया है। भारतीय झंडे वाला जहाज शुक्रवार सुबह गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचा। बीते दिनों भारतीय झंडे वाले दो जहाजों पाइन गैस और जग वसंत ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया था। शिप ट्रेकिंग डेटा के अनुसार, बीते सोमवार को इन दोनों जहाजों को ईरान के लारक और केशम द्वीपों के बीच देखा गया था। ये दोनों जहाज उन 22 भारतीय जहाजों में शामिल थे, जो पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए थे। युद्ध के चले ईरान ने होर्मुज को आंशिक रूप से बांधित कर दिया है, जिसके चलते पूरी दुनिया में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जहाज जग वसंत और पाइन गैस पर 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भरी हुई है। जहाज जग वसंत पर 33 भारतीय नाविक सवार हैं।

सेमीकंडक्टर सालाई चैन पर अमेरिका का बड़ा दांव

नई दिल्ली। वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश विभाग ने 250 मिलियन डॉलर के पैक्स सिलिका फंड की घोषणा की है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह पहल कांग्रेस के साथ मिलकर विदेशी सहायता फंडिंग के जरिए लागू की जाएगी। यह फंड खास तौर पर उन अहम क्षेत्रों पर फोकस करेगा, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाते हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का खनन और प्रोसेसिंग, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार। इसका उद्देश्य वैश्विक सप्लाई चैन को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थानीयों के प्रति लचीला बनाना है। फंड का एक अहम उद्देश्य पारंपरिक सहायता मॉडल से आगे बढ़ना भी है।

पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया

हर्ष ती पंत

अमेरिका-ईरान युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक जानी-पहचानी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई को उजागर किया है। वह यह कि जब सैन्य उद्देश्य संरचनात्मक आर्थिक निर्भरताओं से टकराते हैं, तो संघर्ष शायद ही कभी अपने मूल उद्देश्य तक सीमित रहते हैं। शासक को हटाने और परमाणु अप्रसार के खिलाफ सुनियोजित अमेरिकी-इजरायली प्रयास के रूप में 28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की बुनियाद पर कब्जे की एक कहीं ज्यादा गंभीर लड़ाई में बदल गया है।

तनाव बढ़ने की गति चौंकाने वाली रही है। ईरान का 1 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का निर्णय मात्र प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं था, यह वैश्विक संसाधनों को बाधित

करने की उसकी स्थायी क्षमता का एक सुनियोजित प्रदर्शन था। वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) प्रवाह के लगभग पांचवें हिस्से के परिवहन से जुड़ा होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली में सबसे अधिक दबाव को केंद्र बना हुआ है। टैंकरों को रोकने, जीपीएस (जोइबल पोजिशनिंग सिस्टम) को बाधित करने और स्पष्ट धमकियों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण केंद्र का दुरुपयोग करने के ईरान के इरादों ने इस क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक प्रभाव डाला है।

इजरायल द्वारा साउथ पास पर किए गए हमले और उसके बाद कतर के रास लाफान परिसर पर ईरान की त्वरित कार्रवाई पारस्परिक असुरक्षा को लेकर जवाबी तैयारों को दर्शाती है। ये केवल प्रतीकात्मक लक्ष्य नहीं हैं, ये वैश्विक ऊर्जा संरचना के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विशेष रूप से एलएनजी



ढांचे को हुए नुकसान ने यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक आर्थिक स्थिरता को आधार प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को उजागर कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अन्य जगहों पर हुए समानांतर हमलों से यह बात और पुष्ट होती है कि संघर्ष का दायरा व्यापक हो गया है और इसने खाड़ी के संपूर्ण निर्यात तंत्र को अपनी चपेट में ले लिया है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह

है कि निशाना बनाए जाने का दायरा बढ़ता जा रहा है। बंदरगाहों और विलवणीकरण संयंत्रों से लेकर डेटा केंद्रों और हवाई अड्डों तक, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अब संघर्ष के दायरे में आ गए हैं। यह समकालीन युद्ध में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां असैनिक क्षेत्रों से सैन्य परिसंपत्तियों के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में, जहां आर्थिक बुनियादी ढांचा गहराई से एकीकृत है, ऐसे कार्यों से तात्कालिक मानवीय जोखिम और दीर्घकालिक विकास संबंधी बाधाएं, दोनों ही बढ़ जाती हैं।

आर्थिक परिणाम, जैसा कि अपेक्षित था, तीव्र और गंभीर रहे हैं। ऊर्जा बाजार, जो पहले से ही तंग परिस्थितियों में चल रहे थे, अस्थिरता के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कीमतों में उछाल, आपूर्ति में व्यवधान और विमानन से लेकर कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों पर

पड़ने वाले व्यापक प्रभाव इस बात को रेखांकित करते हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता किस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत झटके उत्पन्न कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कड़ी चेतावनी चुनौती की गंभीरता को दर्शाती है, लेकिन यह एक गहरे संरचनात्मक विषय की ओर भी इशारा करती है। यह विषय है भू-राजनीतिक रूप से अस्थिर बने इस क्षेत्र पर दुनिया की निरंतर निर्भरता।

प्रमुख शक्तियों के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चीन की क्तिताएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा में उसकी अधिक मुहुर भूमिका या विविधीकरण के प्रयासों में तेजी आने की संभावना है। यूरोप, जो पहले की ऊर्जा संबंधी बाधाओं के झटकों से अभी भी जूझ रहा है, एक बार फिर असुरक्षा का सामना कर रहा है।

शोभायात्रा के साथ निकला जुलूस और भगवान श्रीराम की झांकियां

रायपुर। रामनवमी के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रायपुर में आमापारा क्षेत्र में झांकी निकाली गई। जंवारा विसर्जन के साथ माता को विदाई दी गई। विसर्जन की वजह से शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं कुछ बच्चे विसर्जन के दौरान तलवार लहराते दिखे।

फूल चौक से आमापारा चौक और कंकाली तालाब रोड तक लंबा जाम देखने को मिला, जबकि आजाद चौक, शारदा चौक से लेकर पुरानी बस्ती तक ट्रैफिक डायवर्जन की स्थिति बनी रही। इसके अलावा रायपुर में हनुमान चालीसा महापाठ का भव्य आयोजन होगा। जिसका लाइव प्रसारण 100 देशों में किया जाएगा। एक ही समय में कई देश



के श्रद्धालु सामूहिक रूप से जुड़ेंगे।

बिलासपुर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। व्यंकटेश मंदिर सिम्स चौक से शुरू हुई इस यात्रा का जगह-जगह स्वागत हुआ। शोभायात्रा में सबसे आगे संकेटमोचन हनुमान का विशालकाय प्रतिमा आकर्षक का केंद्र रही। रायगढ़ के नटवर स्कूल

से रामनवमी की शोभायात्रा की शुरुआत हुई, जो तय रूट के अनुसार स्टेशन चौक से होते हुए एमजी रोड तक निकली। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कीं और कई जगहों पर हैरतअंगोज करतब भी दिखाए गए। शोभायात्रा में हजारों की संख्या में रामभक्त शामिल हुए, जहां भजन और जय श्रीराम के नारों से

माहौल गुंजात रहा।दुर्ग शहर के 250 साल पुराने श्री राम पंचायती मंदिर में 108 परिक्रमा कर भगवान की पूजा की गई। यहां 50 हजार भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है।

मंदिरों में जयकारे गूजे

रामनवमी के अवसर पर बिलासपुर के श्री वेंकटेश मंदिर में सुबह 5:30 बजे सुप्रभातम और उत्थापन आरती से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 8 बजे भगवान का अभिषेक किया गया और 9 बजे से 12 बजे तक भजन-कीर्तन हुआ।दोपहर 12 बजे भगवान श्रीराम के जन्म के समय मंदिर में जय श्रीराम के जयकारे गूज उठे। शाम 4 बजे से भगवान की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे शहर में

घूमते हुए रात करीब 8.45 बजे वापस मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद महाआरती की जाएगी। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हनुमान चालीसा महापाठ होगा। यह कार्यक्रम श्री हनुमान महापाठ समिति की ओर से लगातार 18वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी के माध्यम से देश दुनिया में किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, रायपुर के साथ ही देशभर के करीब 2000 स्थानों पर एक ही समय में श्रद्धालु सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे यह आयोजन वैश्विक स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त करेगा।

स्वयं से पहले आप के मूल मंत्र को अपनाना होगा: गिरीश चंदेल



रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की 21वीं बैठक का आज यहां कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभाकक्ष में आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं युवा सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।कुलपति डॉ गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की शुरुआत अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा द्वारा स्वयं से पहले आप के प्रेरणादायक संदेश के साथ की गई। उन्होंने स्वच्छता को जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा

बनाने पर जोर दिया।

इसके पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य समन्वयक डॉ. नीता बाजपेयी ने रक्तदान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसके प्रति जन-जागरूकता आवश्यक है। डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता को जन-अभियान के रूप में संचालित करने का सुझाव देते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। जल संरक्षण के संदर्भ में यह चिंता को जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा

कारण जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं तथा लगभग 30 फीसदी पेयजल व्यर्थ हो रहा है।

इस पर समाधानात्मक पहल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने तथा प्लास्टिक बोतलों के प्रयोग को कम करने का संकल्प भी लिया गया। डॉ. रत्ना नशीने ने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अबुल्लामाडू में पीस मैराथन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वीड मैनेजमेंट, टीकाकरण कार्यक्रम एवं मिलेट्स मिशन जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया। प्रशिक्षण एवं उपलब्धियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

डॉ. स्नेहलता पाठक को मिला दिल्ली में त्यंग्य यात्रा सम्मान

रायपुर। विगत 21 मार्च को दिल्ली में डॉ. प्रेम जनमेजय जी की व्यंग्य यात्रा के बैनर तले देश के कई व्यंग्यकार सम्मानित हुए, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की स्थापित साहित्य एवम् व्यंग्यकार डॉ. स्नेहलता पाठक को निरंतर व्यंग्य? लेखन के? क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाने पर शारदा त्यागी व्यंग्य यात्रा सम्मान से स्मृति चिन्ह एवम् प्रशस्ति पत्र देकर डॉ. प्रेम जनमेजय- अध्यक्ष प्रबंध समिति, रणविजय राव-महासचिव प्रबंध समिति एवम् ममता कालिया- अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा सम्मानित किया गया. ज्ञात हो कि डॉ. स्नेहलता पाठक ने लगभग 12 व्यंग्य संग्रह, लाल रिबन वाली लड़की एक उपन्यास और दीप शिखा कहानी संग्रह जैसी पुस्तकों का सृजन किया है।



हुए सम्मान पर वलंड ब्राम्ण फंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुननिधि मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ओझा, प्रदेश महासचिवद्वय अजय अवस्थी, डॉ. सुनील कुमार ओझा, संभागीय अध्यक्ष नितिन कुमार झा, प्रदेश सलाहकार रज्जन अग्निहोत्री, युवा अध्यक्ष अविनय दुबे, महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा, महिला महासचिव सुमन मिश्रा, राघवेन्द्र पाठक, रामवृत्त विवारी, अभिषेक त्रिपाठी, सतीश शर्मा, उमेश शर्मा आदि ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

सीएम साय ने नन्हीं बेटियों का विधि-विधान से किया पूजन

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामनवमी के पावन अवसर पर बगिया स्थित अपने निवास में देवी स्वरूपा नन्हीं बेटियों का विधि-विधान से पूजन किया और अपने हाथों से उन्हें प्रसाद अर्पित किया। यह परंपरा हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा निभाई जाती है और इसे प्रदेश में नारी शक्ति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बेटियों केवल पूजनीय ही नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज और भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस परंपरा के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया जाता है कि बेटियों का सम्मान, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा हमारी सांस्कृतिक और नैतिक ज़िम्मेदारी है।



विष्णुदेव साय ने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा से प्रदेश की प्रत्येक बेटी को शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करें। उनका यह संदेश न केवल परिवारों को बेटियों के प्रति सजग करने वाला है, बल्कि यह नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में बेटियों की अग्रणी भूमिका को भी रेखांकित करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेटियों के विकास, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। बेटियाँ हमारे समाज

की उज्ज्वल धरोहर हैं और उनकी प्रतिभा, शिक्षा और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को यह भी याद दिलाया कि बेटियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा केवल पारंपरिक पूजन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन में भी निभाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेटियों का शिक्षित और सशक्त होना प्रदेश और राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नन्हीं बेटियों को प्रसाद अर्पित करना और उनके सम्मान का यह दृष्टांत स्थानीय समाज में नारी शक्ति के महत्व को उजागर करता है। यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और नैतिक संदेश भी देता है कि बेटियाँ हमारे भविष्य की मजबूत नींव हैं।

उद्योग मंत्री ने कोलमैन की प्रतिमा का किया अनावरण

रायपुर।

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज शुक्रवार को उद्योग मंत्री ने कोलमैन की प्रतिमा का अनावरण किया।



प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज शुक्रवार को उद्योग मंत्री ने कोलमैन की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रसिद्ध लाईन में मिनी गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। इसी प्रकार पुष्पलता उद्यान के सामने सड़क डिवाइडर प्लांटेशन जरीसेवा में समर्पित हुआ। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत उपस्थित थी।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर की व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ शहर का सौंदर्यीकरण कर इसे संजाने, संचारने की दिशा में नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं, एक ओर जहां शहर की स्वच्छता

द्वारा शहर के रोड डिवाइडरों में मल्टीकलर फूलों के पौधे रोपित कर डिवाइडरों को मल्टीकलर फूलों से सजाने संचारने का कार्य भी हो रहा है, इस कड़ी में निगम द्वारा सुभाष चौक पुष्पलता उद्यान से कोसबाड़ी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोड डिवाइडर में इमोजी थीम के अंडाकार गमलों में वोगनवेलिया तथा यूफारबिया मल्टीकलर फूलों के पौधे लगाये गये हैं, इन्हें भी आज जनसेवा में समर्पित किया गया।

इस मौके पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद अशोक चावलानी, अजय गोंडू, पंकज देवांगन, वैभव शर्मा, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव, मनोज सिंह राजपूत उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

चुनावी राज्यों के मतदान से डर कर डीजल, पेट्रोल से एक्साइज घटाया: बैज

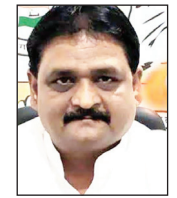
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए डीजल, पेट्रोल पर से स्पेशल एडिशनल एक्साइज को कम किया है, इसका लाभ केवल तेल कंपनियों को होगा। जैसे ही बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी में चुनाव खत्म हो जाएंगा, भाजपा सरकार तुरंत पेट्रोल, डीजल के दामों को 5 से 10 रुपये बढ़ा देगी, यह चुनावी डर से तेल कंपनियों को यह राहत दी गई है। यह पहली बार



नहीं हो रहा, मोदी सरकार इसके पहले भी विभिन्न राज्यों के मतदान के बाद डीजल, पेट्रोल एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य और टैक्स बढ़ा चुकी है। यह जनता को लूटने वाली सरकार है। यह अपने चुनावी नफे, नुकसान के हिसाब से निर्णय लेती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डीजल को स्पेशल एडिशनल एक्साइज मुक्त तथा पेट्रोल पर एक्साइज में 10 रु. की कटौती कर मोदी सरकार ने जनता पर अहसान नहीं किया है। मोदी सरकार 2020 से लेकर अभी तक डीजल, पेट्रोल पर बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी लगा कर 12 साल में 44 लाख करोड़ रु. की कमाई आम जनता से किया है। कोरोना काल में डीजल पर 30 और पेट्रोल पर 35 रु. की एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने मूल्यों के युक्तिकरण के नाम पर लगाया था।

मंत्री को लाभ पहुंचाने हितों को दरकिनार किया गया: शुक्ला

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री को लाभ पहुंचाने सरकार ने राज्य के हितों को दरकिनार कर दिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ इस टैंडर में कमीशनखोरी का बड़ा खेल हुआ है। यह टैंडर छत्तीसगढ़ में सरकार प्रायोजित लूट का बड़ा उदाहरण है। भाजपा सरकार में संगठित लूट का गिरोह चल रहा है, राष्ट्रीय पदाधिकारी उसके सरगना



है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आबकारी विभाग में मेनपावर सप्लाई का 300 करोड़ रु. टेंडर हुआ, जिसमें 148 कंपनियों ने भाग लिया। जिसमें से 8 कंपनी चयनित हुई, इसमें से दो कंपनी एसआईएस कैश सर्विसेस लिमिटेड तथा डस्टर टोटल सॉल्यूशन सर्विसेस प्रा. लि. एक मालिक की है। दोनों के मालिक भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री है, जो गुजरात से आते हैं। यह पहली बार नहीं है, पहले भी वनरक्षक भर्ती और पुलिस अराक्षक भर्ती प्रक्रिया में संधियों के द्वारा संचालित हैदराबाद की अनुभवहीन आईटी कंपनी को शामिल करके बड़े पैमाने पर धोखे की गयीं, छत्तीसगढ़ के युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकार को बेचा गया, फिजिकल परीक्षा के अंकों में गड़बड़ी की गयी।

1500 करोड़ की लेन देन पर पर्दा करने निर्दोष पर कार्यवाही

रायपुर। 1500 करोड़ रु की लेंन देन वीडियो पर असल आरोपी को बचाने निर्दोष पर कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा असल आरोपी भाजपा कद्दावर नेता एवं बाहर से आये नेता के द्वारा दिल्ली के बड़े नेता से 1500 करोड़ रु. की मांग करने का वीडियो बनवाकर जारी किया गया था। ये जांच की खुलासा हुआ।फकड़े गये आरोपी का सम्बंध भी इन्ही नेताओं से निकला एवं आरोपियों के द्वारा ही



भाजपा एवं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया को हैडल करने की जानकारी भी सामने आयी है। आरोपियों ने स्वीकार भी किया बड़े नेताओं के कहने पर ही उनके द्वारा ही रां मटेरियल देकर वीडियो बनवाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जांच में दूध का दूध पानी हो गया है। फिर असल आरोपी भाजपा के बड़े नेताओं पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? निर्दोष लोगों पर कार्यवाही कर बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार में प्रदेश दिल्ली गुजरात वाले नेताओं का चारागाह बन गया है। भाजपा के बड़े नेता जिन्होंने ये वीडियो बनवाया वही लोग डील करते थे। 1500 करोड़ रु. की मांग की जानकारी उन्ही नेताओं के पास थी।

सरकार नशे में और नशे के लिये चल रही : वंदना

रायपुर। केशकाल में गांजे की खेती के खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि अफीम की खेती के बाद गांजे की खेती का पकड़ाना बताता है कि सरकार नशे में चल रही है और नशे के लिये चल रही है। मादक पदार्थ गांजे, अफीम की खुले आम खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस खेती के पीछे सरकार का संरक्षण है। जो मामले पकड़ा रहे वह जनजागरूकता के



कारण पकड़ा रहे सरकार गांजे, अफीम की खेती करने वाली को संरक्षण दे रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि राज्य में अफीम, गांजे की खेती की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। बिना सरकार के संरक्षण के पूरे प्रदेश में नशे का इतना बड़ा कारोबार संभव नहीं है। भाजपा में निनायक तात्प्रकार को केवल निलंबित किया है।

पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन धान जाम : वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केन्द्रो से मीलोरो को मीलिंग के लिये धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में निलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केन्द्रो में जमा पड़ा है। अकेले बेमेतरा जिले में 7 लाख



मीट्रिक टन से अधिक धान जाम पड़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जब मीलर सरकार से अनुबंध के तहत धान लेने को तैयार है। फिर सरकार धान को मिलर्स को क्यों सौंप नहीं रही है? जितने लंबे समय तक धान संग्रहण केन्द्रों में रखा जायेगा, उतना ही भ्रष्टाचार का जोखिम बढ़ेगा और उतना ही धान खराब होने और वजन कम होने का खतरा रहेगा, यानी हर दिन के साथ सरकार खुद अपने नुकसान को बढ़ा रही है। जितने लंबे समय तक धान खुले में पड़े रहेगा, नमी का मौसम का असर धान पर पड़ेगा। गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाईश बढ़ेगी तथा एक बार फिर से चूहों पर ज़िम्मेदारी थोपी जायेगी।जब सरकार को ये सारे जोखिम पहले से पता है, तब मिलर्स धान लेने को तैयार है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026

भारोत्तोलन का धमाकेदार जलवा, पूर्वोत्तर के सितारों ने

रायपुर> पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के भारोत्तोलन इवेंट ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। 27 मार्च को सीनियर वर्ग की तीन स्पर्धाओं में पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि छत्तीसगढ़ समेत अन्य टीमों ने कड़ी चुनौती दी। देशभर से आई आदिवासी प्रतिभाओं ने ताकत के साथ कुश्ती के दांव-पेच और तकनीक का अनुपम प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया।



क्लीन एंड जर्क में 149 किग्रा के साथ कुल 269 किग्रा उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मिजोरम के लालफाकवमा ने 265 किग्रा (सैच 119, क्लीन एंड जर्क 146) से रजत और जैकब वानलालतुआंगा ने 250 किग्रा से कांस्य हासिल किया। ओडिशा के के. सिमांचल चौथे, अरुणाचल के

महिला 63 किग्रा में ओडिशा की बिटु रिमता भोंई ने कुल 195 किग्रा के दमदार लिफ्ट से स्वर्ण जीता। अरुणाचल की बोनी

मांकख्या 193 किग्रा से रजत पर रहीं, जबकि असम की दुंखम संग तुरंग ने 161 किग्रा से कांस्य लिया। असम की रुमे मेच 145 किग्रा से चौथी, अंडमान-निकोबार की तान्याशा 140 किग्रा से पांचवीं तथा छत्तीसगढ़ की हेमा मांडवी 132 किग्रा से छठी रहीं। ओडिशा की करमप्रिय मुरमु (125), त्रिपुरा की ममानो शीला (105), मध्यप्रदेश की शीला डामोर (88) और अरुणाचल की बोम्पी बागरा (85) ने सातवें से दसवें स्थान हासिल किए।

पुरुष 71 किग्रा वर्ग में मिजोरम के सिक्वन बेब्लेधाटलो ने कुल 281 किग्रा उठाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कर्नाटक के मंजूनाथ मराठी ने 270 किग्रा से रजत तथा अरुणाचल के तायर रोनिन ने 255 किग्रा से कांस्य जीता। झारखंड के हर्षित बागे, असम के मानस ज्योति और केरल के श्रीकृट्टनकृट्टन भी प्रभावशाली रहे। महिला 58 किग्रा में अरुणाचल की अनाई वांम्सू ने सैच 74 किग्रा और क्लीन एंड जर्क 95 किग्रा के साथ 169 किग्रा कुल वजन से स्वर्ण जीता। ओडिशा की मिना सांता ने 165 किग्रा से रजत तथा मीना सिंह ने 161 किग्रा से कांस्य हासिल किया। असम की मार्टिना मिली, तारा सोनवाल और आंध्र की जी. लेनिन एस प्रिया ने भी कड़ी टक्कर दी।

कर्नाटक का स्वर्णिम प्रदर्शन तैराकी में पूर्ण वर्चस्व

रायपुर।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन कर्नाटक ने अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। कर्नाटक 10 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला राज्य बन गया है। तीसरे दिन के अंत तक कर्नाटक को कुल 13 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक हो गए हैं, जिनमें सभी स्वर्ण पदक तैराकी स्पर्धाओं से प्राप्त हुए हैं।



कर्नाटक के स्टाेर तैराक मणिकांता एल ने लगातार उकृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरे दिन दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए। अब तक वे कुल आठ

जबकि असम 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ त्रिपुरा के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर बना हुआ है। मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य के लिए एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। अनुष्का भगत ने महिलाओं की 50 मीटर बेकस्ट्रोक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना तीसरा रजत हासिल किया, जबकि निखिल जाल्को ने पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में कांस्य पदक जीता।